मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं नई दिल्ली से एक साथ प्रकाशित दैनिक समाचार-पत्र

हमारा उद्देश्य सेवा समर्पण जनकल्याण

दीपावली

एक सत बुलेटिन

E-mail: eksatbulletin@gmail.com | भोपाल, रविवार 08 नवंबर 2026 | वर्ष-08, अंक-354, पृष्ठ-08, मूल्य- दो रुपए | Website: www.eksatbulletin.in

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ओरछा में किये भगवान श्री रामराजा सरकार के दर्शन

श्री रामराजा सरकार का मंदिर आस्था और श्रद्धा का प्रमुख केंद्र

एक सत बुलेटिन, भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को छोटी दीपावली पर निवाड़ी जिले की धार्मिक एवं पर्यटन नगरी ओरछा में विश्व प्रसिद्ध श्रीरामराजा सरकार मंदिर पहुंचकर दर्शन एवं विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। उन्होंने श्रीरामराजा सरकार के मनोहारी स्वरूप के दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, प्रगति और खुशहाली की प्रार्थना की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ओरछा का श्रीराम राजा मंदिर हम सभी के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। हमारी सरकार बनने के बाद श्रीरामराजा लोक के विकास एवं निर्माण के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से ओरछा एक अद्भुत स्थल है। इसका अत्यंत ऐतिहासिक महत्व भी है, ओरछा आकर सबका मन यहीं का हो जाता है।



मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में काशी में भगवान विश्वनाथ धाम, अयोध्या में भगवान श्रीराम धाम तथा उज्जैन में श्री महाकाल महालोक के विकास से धार्मिक पर्यटन को नई पहचान मिली है। मध्यप्रदेश में भी धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के विकास का वातावरण बना है। ओरछा में भी इसी प्रकार की समृद्धि और विकास लाने के लिए राज्य सरकार कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्रीराम राजा सरकार के दर्शन एवं पूजन के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि ऐसी मान्यता है कि भगवान श्रीराम दिन में ओरछा में राजा के रूप में विराजमान रहते हैं। भगवान श्रीराम हम सभी के आराध्य हैं, और हम सब उन्हें श्रद्धा से नमन करते हैं। दीपावली के पावन पर्व से एक दिन पूर्व रूप चौदस के अवसर पर ओरछा आकर श्रीरामराजा सरकार के दर्शन एवं नमन करने का सौभाग्य मिला है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भगवान श्रीराम से प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं सभी के कल्याण की कामना करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्थानीय उत्पादों एवं बुंदेली कला को सराहा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ओरछा में हाथी साव सुपारी साव परिसर में लगाई गई विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनी में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों पर पहुंचकर स्थानीय इतिहास, संस्कृति, पारंपरिक खाद्य उत्पादों, औषधीय फसलों एवं स्थानीय कला से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदर्शनी में शामिल सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए प्रत्येक प्रदर्शनी स्टॉल के प्रतिभागियों को 5-5 हजार रुपये की नगद पुरस्कार राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदर्शनी में प्रदर्शित मानचित्र का अवलोकन किया तथा सीतामढ़ी सहित क्षेत्र के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय जन जीवन, क्षेत्र की विशेषताओं एवं परंपराओं के संबंध में भी जानकारी ली।

ईरान ने अमरीका को भेजा नया परमाणु प्रस्ताव

सात शर्तें नहीं मानीं तो होर्मुज नहीं खुलेगा

एजेन्सी, तेहरान



ईरान और अमरीका के बीच जारी तनाव के बीच बातचीत की नई कोशिश शुरू हुई है। ईरान ने कतर के जरिए अमरीका को एक परमाणु प्रस्ताव भेजा है। मीडिया से बात करने वाले एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने यह जानकारी दी। हालांकि, ईरान ने साफ कर दिया है कि इस प्रस्ताव पर बातचीत तभी होगी, जब अमरीका उसकी सात मांगें पूरी करेगा। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी मोहसिन रजाई ने भी अपनी शर्तों को दोहराया।

रूस दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि ईरान ने अमरीका के सामने सात शर्तें रखी हैं, जब तक अमरीका इन शर्तों को पूरा नहीं करता, तब तक न तो होर्मुज स्ट्रेट खोला जाएगा और न ही किसी भी तरह की बातचीत होगी। ईरान की मांगों में अमरीकी प्रतिबंध हटाना, विदेशों में फ्रीज की गई ईरानी संपत्ति जारी करना और युद्ध का हजार्ना देना शामिल है। इसके अलावा ईरान ने अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी खत्म करने और क्षेत्र से अमरीकी सेना की वापसी जैसी मांगें भी रखी हैं। ये शर्तें ईरान की ओर से रखी गई हैं।

ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह तैयार: ट्रंप

अमरीका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि अमरीका ईरान में संभावित अभियान शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और अमरीकी सेना पहले की तुलना में कहीं अधिक हथियार बना रही है। अगर हमें ईरान के मामले में आगे की कार्रवाई करनी पड़ी, तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम फैसला लेंगे।

भाजपा ने कांग्रेस पर कसा तंज; अखिलेश को भी घेरा

'आतंकियों के लिए रोने वालों को कश्मीर क्यों नहीं दिखा'

एजेन्सी, नई दिल्ली

दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर 1992 की घटना पर सोनिया गांधी के आंसू बहने की खबर से कांग्रेस पार्टी का राम विरोधी चेहरा एक बार फिर देश के सामने आ गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह वही आंखें हैं जो बटला हाउस एनकाउंटर के आतंकियों के लिए भी रोई थीं। त्रिवेदी ने सवाल उठाया कि जब 1990 में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ, तब कांग्रेस के नेताओं की आंखों से आंसू क्यों नहीं निकले? उन्होंने विवादित ढांचे को फिर से बाबरी मस्जिद कहे जाने पर भी गहरी आपत्ति जताई।



सोनिया गांधी को लेकर क्या कहा?

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 को सोनिया गांधी ने आखिर किस भारतीय टीवी चैनल पर ऐसी तस्वीरें देख लीं जिससे उनकी आंखों में आंसू आ गए? उन्होंने उस दिन का पूरा घटनाक्रम बताते हुए कहा कि कारसेवक सुबह 11:30 बजे परिसर में घुसे थे, शाम पांच बजे ढांचा ढहने के बाद कल्याण सिंह सरकार ने इस्तीफा दिया और रात 8:45 बजे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने यूपी सरकार की बर्खास्तगी का एलान किया था। उन्होंने याद दिलाया कि 1989 में दिवंगत राजीव गांधी ने अपना चुनाव प्रचार अयोध्या से भगवान राम का नाम लेकर शुरू किया था, जबकि आज की कांग्रेस गाजा के प्रति संवेदना जताती है और आतंकियों के लिए रोती है, जो उनकी कट्टरपंथी मानसिकता को उजागर करता है।

अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के 12 दिसंबर को प्रस्तावित अयोध्या दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रवक्ता ने इसे चुनावी नाटक करार दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव करीब आते ही ऐसे प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। यह वही दल है जिसके संस्थापकों ने कारसेवकों पर गोलियां चलवाई थीं और जिनके नेता कहते थे कि गुंबद पर चढ़े लोग वहां फंस गए थे। भाजपा सांसद त्रिवेदी ने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के पुराने बयान का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने 16 हिंदुओं को मरवाया था, इससे ज्यादा और क्या कर सकता था।

लद्दाख: 13 हजार फीट की ऊंचाई पर भारतीय वायुसेना ने किया कमाल

चीन सीमा के पास उतरा आईएल-76एमडी विमान

एजेन्सी, नई दिल्ली



भारतीय वायुसेना के रूसी मूल के IL-76MD परिवहन विमान ने लद्दाख के न्योमा एयरबेस पर सफल लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। करीब 13 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित यह एयरबेस चीन के साथ एलओसी से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। वायुसेना ने इसे भारत की रणनीतिक हवाई क्षमता के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है।

रूस में बना भारतीय वायु सेना का एक परिवहन विमान लद्दाख के न्योमा एयर बेस पर सफलतापूर्वक उतरा। वायु सेना के अनुसार, यह दुनिया भर में इस विमान द्वारा की गई अब तक की सबसे अधिक ऊंचाई वाली लैंडिंग है।

यह एयरबेस कितनी ऊंचाई पर है?

यह एयरबेस लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। चीन के साथ लगी 'लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल' (एलओसी) से लगभग 25 किमी की दूरी पर है। भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने सोशल मीडिया पर बताया, 'भारतीय वायु सेना के एक IL-76MD विमान ने न्योमा में सफलतापूर्वक लैंडिंग करके इतिहास रच दिया है। यह दुनिया भर में इस विमान द्वारा की गई अब तक की सबसे ऊंचाई वाली लैंडिंग है।'

वायु सेना ने क्या बताया?

वायु सेना ने कहा, 'यह विमान की बेहतरीन क्षमता का एक शानदार प्रदर्शन है, जिसमें इसके चालक दल (क्रू) का असाधारण कौशल, सटीकता और पेशेवर रवैया शामिल है।' आईएएफ ने इस लैंडिंग को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया, जो भारत की रणनीतिक एयरलिफ्ट क्षमता को और मजबूत करती है।'

IL-76MD असल में क्या है?

IL-76MD चार इंजन वाला एक बड़ा (वाइड-बॉडी) रणनीतिक भारी मालवाहक विमान है। इसे मूल रूप से सोवियत संघ में बनाया गया था और यह 40 से 50 टन तक का सामान ले जाने में सक्षम है। इसमें टैंक, तोपें, बख्तरबंद गाड़ियां और यहां तक कि पूरे फील्ड अस्पताल भी ले जाए जा सकते हैं। इस विमान को बारीकी या नजाकत के बजाय बड़े पैमाने पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया था।

बंगलूरू से लखनऊ जा रही थी फ्लाइट

बंगलूरू एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित: इंडिगो फ्लाइट में मिला हाईजैक की धमकी वाला नोट

एजेन्सी, बंगलूरू

कर्नाटक की राजधानी बंगलूरू से लखनऊ जा रही इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6ए-451 में शनिवार को हाईजैक की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। विमान के वॉशरूम में धमकी भरा एक नोट मिला था। इसके बाद पायलटों ने एहतियात के तौर पर विमान को वापस बंगलूरू ले जाने का फैसला किया। इस घटना के बाद केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 पर फुल इमरजेंसी घोषित कर दी गई।

वॉशरूम में मिला हाईजैक की धमकी वाला नोट

जानकारी के मुताबिक, विमान बंगलूरू से लखनऊ के लिए रवाना हुआ था। उड़ान के दौरान चालक दल के सदस्यों को विमान के वॉशरूम में हाईजैक की धमकी वाला नोट मिला। इसके बाद पायलटों ने तय सुरक्षा प्रक्रिया का पालन करते हुए



तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना दी और विमान को वापस बंगलूरू मोड़ दिया।

एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित

विमान के हवाई अड्डे पर उतरने के बाद सुरक्षा कर्मियों और विमानन सुरक्षा एजेंसियों ने उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद विमान को अलग स्थान पर खड़ा कर उसकी गहन जांच शुरू की गई। सुरक्षा एजेंसियां विमान में किसी संदिग्ध वस्तु या तोड़फोड़ की आशंका को देखते हुए जांच कर रही हैं। इंडिगो के प्रवक्ता ने बताया कि 7 नवंबर 2026 को बंगलूरू से लखनऊ जा रही फ्लाइट 6ए-451 में सुरक्षा खतरे की सूचना मिली थी। तय प्रक्रिया के तहत संबंधित अधिकारियों को तुरंत जानकारी दी गई। जरूरी सुरक्षा जांच के लिए विमान को वापस बंगलूरू लाया गया।

एयरलाइन ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद जताया है। यात्रियों को जलपान दिया जा रहा है और उड़ान से जुड़ी जानकारी लगातार साझा की जा रही है। इंडिगो के मुताबिक, जरूरी सुरक्षा जांच पूरी होने और संबंधित अधिकारियों से मंजूरी मिलने के बाद विमान दोबारा लखनऊ के लिए रवाना होगा। फिलहाल जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि धमकी भरा नोट किसने लिखा और इसे विमान के वॉशरूम में किसने रखा था।

उपराष्ट्रपति-सीएम योगी समेत कई मंत्री मौजूद रहे

अयोध्या में 30 लाख दीये जलाए, आतिशबाजी हुई : लेजर शो से रामायण दिखाई गई

एजेन्सी, नई दिल्ली

अयोध्या में 10वां दीपोत्सव मनाया गया। सरयू नदी के किनारे 56 घाटों पर करीब 30 लाख दीये जलाए गए। राम की पैड़ी और सरयू घाट पर लेजर शो से रामायण दिखाई गई। 2100 ड्रोन से विशेष शो किया गया। सरयू तट पर 2147 अर्चकों ने सरयू की महाआरती की। इसके बाद आतिशबाजी की गई। इसके पहले अयोध्या में करीब 3 घंटे तक शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें 21 झांकियां शामिल रहीं। इनमें रामायण के सात कांडों को दशार्या गया था। दीपोत्सव देखने के लिए मुंबई, गुजरात और बिहार सहित देशभर से लोग पहुंचे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और सीएम योगी समेत कई मंत्री भी मौजूद रहे।

रामनगरी में दीपोत्सव के दौरान रामायण प्रसंगों की भव्य प्रस्तुति हुई। पुष्पक विमान पर सवार प्रभु श्रीराम के अयोध्या की ओर प्रस्थान का दृश्य आकर्षण का केंद्र रहा। इस प्रसंग के जरिए लंका विजय के बाद



हर साल दीपों की संख्या बढ़ी

सीएम योगी ने कहा- 2017 में यूपी की अर्थव्यवस्था जर्जर हालत में थी। कर्मचारियों को वेतन देने तक के लिए पैसा नहीं था। पिछली सरकारों के सिंडिकेट ने खजाने पर डकैती डालकर विदेशों में अपने लिए संपत्तियां खरीदी थीं। पहले दीपोत्सव में महज 25 हजार दीप जलाए गए थे। जैसे-जैसे दीपों की संख्या बढ़ी, प्रदेश की समृद्धि भी बढ़ती गई। इस बार अयोध्या में 36 लाख दीप जल रहे हैं, जो प्रदेश की आर्थिक समृद्धि का भी प्रतीक है।



भगवान राम की अयोध्या वापसी को दशार्या गया।

आतिशबाजी से जगमगाई अयोध्या

अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर आसमान रंग-बिरंगी आतिशबाजी से जगमगा उठा। रामनगरी में हो रही आतिशबाजी ने उत्सव का उल्लास और बढ़ा दिया। आसमान में छूटती रंग-बिरंगी रोशनी के बीच सरयू तट और राम की पैड़ी का नजारा देखने लायक रहा। बड़ी संख्या में मौजूद लोग आतिशबाजी का आनंद ले रहे हैं।



विदेशियों ने भी दीपदान किया

शिकागो से अयोध्या आए पॉल और शेल्बे ने भी सरयू तट पर दीये जलाए। उन्होंने बताया कि अयोध्या की बहुत महिमा सुनी है। माता-पिता से रामनगरी के बारे में सुनकर अयोध्या आने का मन बनाया था। आज हमारी यह इच्छा पूरी हो गई।

एक ही बिल्डिंग में स्कूल और शराब दुकान के संचालन पर हाईकोर्ट सख्त, कलेक्टर को 10 दिन की मोहलत

शिकायतों के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई, हाईकोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ता, 16 नवंबर को फिर होगी मामले की सुनवाई

एक सत बुलेटिन, जबलपुर

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने जबलपुर के संजीवनी नगर में एक ही इमारत में स्कूल और शराब दुकान संचालित होने के मामले को गंभीरता से लिया है। मुख्य न्यायाधीश यशवंत कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की संयुक्तपीठ ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर कलेक्टर को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कलेक्टर से कहा है कि मामले की जांच के लिए गठित समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर 10 दिन के भीतर निर्णय लिया जाए। साथ ही अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 नवंबर 2026 की तारीख निर्धारित की है। मामला जबलपुर के संजीवनी नगर मुख्य मार्ग पर स्थित एक भवन का है, जहां एक ही इमारत के अलग-अलग हिस्सों में शराब दुकान और स्कूल संचालित होने का आरोप लगाया गया है। याचिका के अनुसार, भवन के एक हिस्से में शराब दुकान चल रही है, जबकि दूसरे हिस्से में संस्कार



भारती नामक स्कूल संचालित हो रहा है। इस स्थिति को लेकर स्थानीय स्तर पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि शैक्षणिक संस्थान और शराब दुकान का एक ही भवन में संचालन निर्धारित नियमों और आबकारी प्रावधानों के विपरीत है। संजीवनी नगर निवासी अजय पटेल ने इस मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में बताया गया है कि मुख्य मार्ग पर स्थित संबंधित भवन में किराए से शराब दुकान संचालित की जा रही है। इसी भवन के दूसरे हिस्से में संस्कार भारती स्कूल चल रहा है।

याचिकाकर्ता के मुताबिक, एक ही इमारत में इस तरह स्कूल और शराब दुकान का संचालन नियमों के अनुरूप नहीं है। इसके बावजूद लंबे समय से दुकान का संचालन जारी है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में यह भी उल्लेख किया है कि इस संबंध में जिला कलेक्टर और आबकारी विभाग के अधिकारियों को शिकायतें की गई थीं। शिकायतों के माध्यम से अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया गया था कि स्कूल के साथ ही उसी भवन में शराब दुकान का संचालन हो रहा है। इसके बावजूद शिकायतों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासनिक स्तर पर समाधान नहीं होने के बाद याचिकाकर्ता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इस जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 28 अक्टूबर को संबंधित अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। न्यायालय ने मामले में संबंधित पक्षों से स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। इसके बाद शुक्रवार को मामले की अगली सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुरेंद्र वर्मा उपस्थित हुए, जबकि राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ब्रह्मदत्त सिंह ने पक्ष रखा। फिलहाल इस मामले ने स्कूलों के आसपास और शैक्षणिक संस्थानों के साथ शराब दुकानों के संचालन को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों और अभिभावकों के बीच भी इस तरह की स्थिति को लेकर चिंता जताई जा रही है।

कलेक्टर ने गठित की थी जांच समिति

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जबलपुर कलेक्टर ने जांच के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति ने संबंधित तथ्यों और शिकायतों के आधार पर अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी है। हालांकि, समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद भी कलेक्टर की ओर से उस पर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। सरकार की ओर से दी गई इस जानकारी के बाद संयुक्तपीठ ने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट पर निर्णय लेने में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। न्यायालय ने जबलपुर कलेक्टर को निर्देश दिया कि वे समिति की रिपोर्ट का परीक्षण कर 10 दिन के भीतर अपना निर्णय लें। अदालत के इस निर्देश से अब पूरे मामले में प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की उम्मीद बढ़ गई है। हाईकोर्ट ने कलेक्टर को निर्धारित समय-सीमा में निर्णय लेने के निर्देश देने के साथ ही मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर 2026 को तय की है। अब अगली सुनवाई में यह महत्वपूर्ण होगा कि कलेक्टर जांच समिति की रिपोर्ट पर क्या निर्णय लेते हैं और प्रशासन की ओर से न्यायालय के निर्देशों के पालन में क्या कार्रवाई की जाती है।

दीपावली से पहले पटाखा दुकानों पर पुलिस की सख्ती, सिहोरा और गोसलपुर में अधिकारियों ने किया निरीक्षण

एक सत बुलेटिन, जबलपुर



दीपावली पर्व को देखते हुए जबलपुर जिले में पटाखों के सुरक्षित भंडारण और उनके विक्रय को लेकर पुलिस प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी है। त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना और आगजनी की आशंका को रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों ने पटाखा दुकानों का निरीक्षण शुरू कर दिया है। इसी क्रम में शुक्रवार को पुलिस अधिकारियों की टीम ने सिहोरा और गोसलपुर थाना क्षेत्रों में संचालित पटाखा दुकानों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान दुकानों में सुरक्षा इंतजामों, अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, पटाखों के भंडारण और बिक्री से संबंधित नियमों की जांच की गई। पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनु बेनीवाल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोन-3 मनीष भारद्वाज ने संबंधित थाना क्षेत्रों में पहुंचकर पटाखा दुकानों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने दुकानदारों से सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी ली और मौके पर उपलब्ध संसाधनों का परीक्षण किया। पुलिस का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दीपावली के दौरान पटाखों की बिक्री निर्धारित नियमों के तहत हो और दुकानों में किसी तरह की लापरवाही के कारण दुर्घटना की स्थिति निर्मित न हो। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने दुकानों में अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया। पटाखों की दुकानें आग के लिहाज से संवेदनशील होती हैं, इसलिए वहां आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम होना जरूरी है। अधिकारियों ने दुकानदारों से यह भी जानकारी ली कि आग लगने जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए दुकान परिसर में किस तरह की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पटाखों के सुरक्षित भंडारण की स्थिति का भी जायजा लिया गया। अधिकारियों ने देखा कि दुकानों में पटाखे निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप रखे गए हैं या नहीं।

अज्ञात बदमाशों ने एटीएम की चाबियों सहित कर्मचारी की एक्सिस लूटी

एक सत बुलेटिन, जबलपुर



बरेला थाना क्षेत्र में तीन अज्ञात बदमाशों ने एटीएम की सफाई एवं सुधार का काम करने वाले कर्मचारी पर हमला कर उसकी एक्सिस स्कूटी लूट ली। स्कूटी की डिक्की में एटीएम मशीन और बैंक कक्ष की कुल 27 चाबियां रखी हुई थीं। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध लूट का प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार 25 वर्षीय शैलेन्द्र कुमार मेहरा निवासी बरगीनगर, वर्तमान में कालीमठ मदनमहल में किराये से रहता है और एसबीआई के एटीएम में सफाई एवं सुधार का काम करता है। चार नवंबर की रात वह अपनी एक्सिस स्कूटी क्रमांक एमपी 20 जेडवाई 1361 से धनपुरी बरेला क्षेत्र में एटीएम की सफाई करने जा रहा था। रात करीब 10:30 बजे बब्बा ढाबा के आगे सड़क किनारे स्कूटी खड़ी कर वह कुछ देर के लिए रुका था। इसी दौरान हीरो मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवक वहां पहुंचे और कुछ आगे जाकर वापस लौट आए। पीड़ित जैसे ही अपनी स्कूटी पर बैठा, उनमें से एक युवक ने लोहे की पाइप से उसके सिर पर दो-तीन वार कर दिए। उसके गिरने पर अन्य दोनों युवकों ने भी पत्थर और हाथ-मुक्कों से मारपीट की। हमले में उसके सिर, चेहरे, हाथों और पैर में चोटें आईं। इसके बाद तीनों बदमाश उसकी स्कूटी लेकर शारदा मंदिर की ओर भाग निकले। स्कूटी की डिक्की में एटीएम मशीन की 12 और बैंक कक्ष की 15 चाबियां रखी थीं। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 309(6), 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

हाईकोर्ट ने बदलाव से किया इनकार 17 नवंबर को अगली सुनवाई

पीजी मेडिकल प्रवेश में इन-सर्विस कोटे की 30 प्रतिशत सीमा बरकरार, हाईकोर्ट ने बदलाव से किया इनकार

एक सत बुलेटिन, जबलपुर



मध्यप्रदेश में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों (पीजी मेडिकल) में प्रवेश की काउंसलिंग को लेकर चल रहे विवाद में इन-सर्विस अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने इन-सर्विस कोटे की अधिकतम सीमा 30 प्रतिशत निर्धारित करने संबंधी अपने अंतरिम आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया है। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने न तो पूर्व के अंतरिम आदेश में संशोधन किया और न ही उसे निरस्त किया। इससे फिलहाल पीजी मेडिकल प्रवेश में इन-सर्विस कोटे की 30 प्रतिशत सीमा प्रभावी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे निर्धारित की गई है। मामला चिकित्सा शिक्षा संचालनालय (डीएमई) द्वारा तैयार की गई पीजी मेडिकल प्रवेश की मेरिट सूची से जुड़ा है। भोपाल निवासी डॉक्टर सरबजीत सिंह और डॉक्टर जान्हवी बत्रा ने याचिका दायर कर प्रवेश प्रक्रिया को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि डीएमई ने ओपन और इन-सर्विस श्रेणी की मेरिट सूचियों को आपस में मिला दिया है। इसके चलते करीब 90 प्रतिशत सीटें इन-सर्विस कोटे के अंतर्गत आवंटित की जा रही हैं। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि एमडी और एमएस जैसे स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश का आधार योग्यता और मेरिट होना चाहिए। मौजूदा व्यवस्था के कारण अधिक अंक प्राप्त करने वाले ओपन श्रेणी के मेधावी अभ्यर्थियों को भी अपनी पसंद के बेहतर मेडिकल कॉलेज और सीटें नहीं मिल पा रही हैं। याचिकाकर्ताओं ने इस व्यवस्था को अवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है। मामले की 2 नवंबर को हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की युगलपीठ ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया था कि पीजी मेडिकल प्रवेश में इन-सर्विस कोटे की सीटें 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी आदेश में संशोधन करने और उसे निरस्त करने की मांग को लेकर गुरुवार को दोबारा सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि 2 नवंबर के अंतरिम आदेश के बाद चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने 3 नवंबर को पूरी पीजी मेडिकल काउंसलिंग रोक दी थी। इसके बाद पूर्व आदेश में संशोधन की मांग की गई, लेकिन युगलपीठ ने इसमें कोई बदलाव करने से इनकार कर दिया। ऐसे में इन-सर्विस कोटे की 30 प्रतिशत सीमा संबंधी अंतरिम आदेश फिलहाल प्रभावी रहेगा।

सड़क हादसे में घायल युवक की मौत, एक का अस्पताल में इलाज जारी

जबलपुर। बरगी थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-34 पर मानेगांव के आगे सागर ढाबा के पास हुए सड़क हादसे में घायल एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल अस्पताल में भर्ती है। पुलिस के अनुसार जागृति नगर अमखेरा निवासी 60 वर्षीय दशरथ कोल ने छह नवंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई कि पांच नवंबर की शाम करीब 6:30 बजे उसे फोन पर सूचना मिली थी कि उसका 56 वर्षीय छोटा भाई ओमप्रकाश चौकसे, निवासी मंशी मोहल्ला, टीकाराम पटेल के साथ मोटरसाइकिल पर जबलपुर से बरगी जा रहा था। इसी दौरान मानेगांव के आगे सागर ढाबा के पास उनका सड़क हादसा हो गया। हादसे में घायल ओमप्रकाश को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जबकि टीकाराम पटेल का उपचार मेट्रो अस्पताल में चल रहा है। उपचार के दौरान छह नवंबर की रात करीब 12:50 बजे ओमप्रकाश की मौत हो गई। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हुए मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है

जबलपुर में खुला प्रदेश का पहला संभागीय उच्च शिक्षा कार्यालय, 5.40 करोड़ रुपये से बना भव्य भवन

एक सत बुलेटिन, जबलपुर



राज्य के उच्च शिक्षा विभाग को जबलपुर में अपना नया संभागीय मुख्यालय प्राप्त हो गया है। लगभग 5.40 करोड़ रुपये की लागत से नवनिर्मित 'अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग' के नवीन प्रशासनिक भवन का आधिकारिक लोकार्पण लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह द्वारा किया गया। उल्लेखनीय है कि उच्च शिक्षा विभाग के लिए विशेष रूप से निर्मित यह संपूर्ण मध्य प्रदेश का पहला समर्पित संभागीय कार्यालय है। विभाग व विद्यार्थियों के लिए लंबे समय से थी आवश्यकता लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि जबलपुर संभाग में इस प्रशासनिक भवन की लंबे समय से नितांत आवश्यकता महसूस की जा रही थी। मुख्यमंत्री के विशेष सहयोग से यह निर्माण कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण हुआ है। यह नया केंद्र पूरे संभाग के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के जरिए नई दिशा प्रदान करने के साथ-साथ विभागीय कामकाज और गतिविधियों के विस्तार में ऐतिहासिक भूमिका निभाएगा।

पति की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उठा पीड़िता की निजता का सवाल

पेन ड्राइव पेश कराने के पूर्व आदेशों की वैधता पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता

एक सत बुलेटिन, जबलपुर



मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में पति की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पीड़िता की निजता और आपराधिक प्रक्रिया के पालन से जुड़ा संवेदनशील मामला सामने आया है। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने पूर्व में समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेशों पर प्रथम दृष्टया सवाल उठाते हुए मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि 17 सितंबर और 22 अक्टूबर 2026 को पारित आदेश प्रथम दृष्टया आपराधिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानूनी सिद्धांतों के अनुरूप प्रतीत नहीं होते। मामले में कौस्तुभ पटेल की ओर से दायर जमानत याचिका पर पांच नवंबर 2026 को सुनवाई हुई। इस दौरान पीड़िता स्वयं अदालत में उपस्थित रही। रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर एकलपीठ ने पाया कि पूर्व में समन्वय पीठ ने 17 सितंबर को जांच अधिकारी को एक वीडियो की जांच करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद 22 अक्टूबर को पीड़िता द्वारा प्रस्तुत पेन ड्राइव स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को उसकी सामग्री का सत्यापन कर अगली सुनवाई में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए थे। जस्टिस अग्रवाल की पीठ ने इस प्रक्रिया की वैधानिकता पर प्रथम दृष्टया आपत्ति जताई और सुप्रीम कोर्ट के चर्चित फैसले निपुण सक्सेना एवं अन्य विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य (2019) 2 एससीसी 703 का उल्लेख किया। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि 22 अक्टूबर को समन्वय पीठ के आग्रह पर पेन ड्राइव प्रस्तुत करने के बाद उसके अधिवक्ता उससे नाराज हो गए और उसे अपना मुकदमा स्वयं लड़ने के लिए कह दिया। पीड़िता का यह भी कहना था कि उसने पहले भी अपने अधिवक्ता को संबंधित सामग्री उपलब्ध कराई थी, लेकिन उसे अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सीधा प्रसारण बंद कर दिया गया, ताकि पीड़िता की निजता सुरक्षित रखी जा सके।

अभियोजन मंजूरी से पहले आपत्ति का निराकरण करने के निर्देश

30 हजार की रिश्वत लेते पकड़ी गईं नगर परिषद अध्यक्ष सारिका खटीक को हाईकोर्ट से राहत

एक सत बुलेटिन, जबलपुर



मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने 30 हजार रुपए की कथित रिश्वत लेते लोकायुक्त की गिरफ्त में आई पन्ना जिले की अमानगंज नगर परिषद अध्यक्ष सारिका खटीक की याचिका का निराकरण कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश यशवंत कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की संयुक्तपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि अभियोजन की मंजूरी देने से पहले सक्षम अधिकारी याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत आपत्ति का निराकरण करें। अदालत के इस निर्देश के बाद अब राज्य सरकार के संबंधित अधिकारी को पहले सारिका खटीक की आपत्ति पर विचार करना होगा और उसके बाद अभियोजन की मंजूरी के संबंध में निर्णय लेना होगा। सारिका खटीक पन्ना जिले की अमानगंज नगर परिषद की अध्यक्ष हैं। वह दमोह जिले के हटा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक उमा खटीक की बेटी भी हैं। उनके खिलाफ अप्रैल 2024 में सागर लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेने के आरोप में कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई के बाद से ही मामला चर्चा में रहा है। सारिका खटीक ने लोकायुक्त की कार्रवाई और अधिकारियों के समक्ष अपनी आपत्तियों पर सुनवाई नहीं होने का मुद्दा उठाते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। अप्रैल 2024 में लोकायुक्त ने की थी कार्रवाई प्रकरण के मुताबिक, अप्रैल 2024 में सागर लोकायुक्त की टीम ने अमानगंज नगर परिषद अध्यक्ष सारिका खटीक को राघवेंद्र राज मोदी से 30 हजार रुपए की कथित रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। शिकायतकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया था कि नगर परिषद से संबंधित बिलों के भुगतान के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता का यह भी दावा था कि 30 हजार रुपए देने से पहले 10 हजार रुपए की राशि भी दी जा चुकी थी। शिकायत के आधार पर लोकायुक्त की टीम ने मामले में कार्रवाई की और सारिका खटीक को कथित रूप से रिश्वत लेते हुए पकड़ा। इस कार्रवाई के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों को लेकर कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। हालांकि, सारिका खटीक ने अपने ऊपर लगे रिश्वत लेने के आरोपों को गलत बताते हुए अलग ही पक्ष रखा था। सारिका खटीक का दावा था कि जिस 40 हजार रुपए की राशि को रिश्वत बताया जा रहा है।

लोकायुक्त के वरिष्ठ अधिकारियों को दी थी शिकायत

याचिकाकर्ता सारिका खटीक के अनुसार, लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद उन्होंने अपने पक्ष और आपत्तियों को लेकर लोकायुक्त के डायरेक्टर जनरल सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को आवेदन प्रस्तुत किया था। उन्होंने अधिकारियों को बताया था कि जिस रकम को रिश्वत बताया जा रहा है, वह उनके पति द्वारा ली गई उधार की राशि थी। इसके बावजूद उनके आवेदन पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। सारिका खटीक का आरोप था कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखने और आपत्ति का निराकरण कराने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें अपेक्षित राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करते हुए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। याचिका के माध्यम से उन्होंने अधिकारियों के स्तर पर प्रस्तुत आवेदन पर कार्रवाई नहीं होने का मुद्दा उठाया था। मुख्य न्यायाधीश यशवंत कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की संयुक्तपीठ के समक्ष हुई।

भाजपा-कांग्रेस दोनों को सता रहा तीसरे विकल्प का डर

आदिवासी सियासत में 47 सीटों का गणित, बीएपी और जयस ने बढ़ाई दोनों दलों की चुनौती

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

मध्य प्रदेश की सत्ता का रास्ता आदिवासी अंचलों से होकर गुजरता है। विधानसभा की 47 सीटों पर आदिवासी मतदाता सीधे चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं, जबकि प्रदेश की कई अन्य सीटों पर भी उनकी भूमिका निर्णायक रहती है। यही वजह है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच आदिवासी वोटों को अपने पाले में करने की सियासी होड़ लगातार तेज हो रही है। दिलचस्प यह है कि इस मुकाबले में अब दोनों राष्ट्रीय दलों के सामने चुनौती सिर्फ एक-दूसरे से नहीं है। भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) और जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन (जयस) जैसे नए राजनीतिक विकल्प भी उनके पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की क्षमता दिखा रहे हैं। आदिवासी राजनीति का यही बदलता समीकरण दोनों दलों की बेचैनी बढ़ा रहा है। भाजपा के लिए चुनौती 2018 में हुए नुकसान की पुनरावृत्ति रोकने की है, तो कांग्रेस के सामने 2023 के चुनाव में मिली सीमित सफलता को सत्ता में वापसी के आधार में बदलने का सवाल है। दोनों दल जानते हैं कि आदिवासी मतदाताओं का समर्थन केवल सीटों की संख्या नहीं बढ़ाता, बल्कि प्रदेश की सत्ता का पूरा गणित बदल सकता है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए विधानसभा की 47 सीटें आरक्षित हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में इनमें से भाजपा ने 24, कांग्रेस ने 22 और भारत आदिवासी पार्टी ने एक सीट जीती थी। आंकड़े बताते हैं कि भाजपा को बहुमत मिलने के बावजूद आदिवासी सीटों पर कांग्रेस ने उसे



कड़ी टक्कर दी। यानी आदिवासी अंचलों में भाजपा की स्थिति मजबूत जरूर हुई, लेकिन कांग्रेस का आधार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वहीं बीएपी की एक सीट ने यह संकेत भी दिया कि आदिवासी मतदाता अब परंपरागत राजनीतिक विकल्पों से आगे देखने लगे हैं। इस बदलाव का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि आदिवासी बहुल इलाकों में स्थानीय मुद्दे, नेतृत्व और संगठनों की सक्रियता चुनावी नतीजों पर असर डालती है। जल, जंगल और जमीन के अधिकार, वन उपज का उचित मूल्य, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विस्थापन और स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक समस्याएं यहां के चुनावी विमर्श को प्रभावित करती हैं। ऐसे में केवल राष्ट्रीय नेतृत्व या बड़े राजनीतिक नारों के सहारे इस वर्ग का भरोसा जीतना आसान नहीं है। भाजपा की चिंता की सबसे बड़ी वजह 2018 का विधानसभा चुनाव है। इससे पहले आदिवासी सीटों पर पार्टी का दबदबा रहा था। वर्ष 2003 में सत्ता परिवर्तन के दौरान भी आदिवासी मतदाताओं का समर्थन भाजपा के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ था। उस समय कांग्रेस के परंपरागत आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगाकर भाजपा ने प्रदेश की राजनीति में अपनी मजबूत जगह बनाई थी। लेकिन 2018 में समीकरण पलट गया। आदिवासी मतदाताओं का झुकाव कांग्रेस की ओर हुआ और इसका सीधा असर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर पड़ा। कांग्रेस ने 47 आरक्षित सीटों में से 30 पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा केवल 16 सीटों पर सिमट गई। एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी जीता। इस प्रदर्शन ने भाजपा को सत्ता से बाहर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कांग्रेस के सामने भी आसान नहीं वापसी की राह

दूसरी ओर कांग्रेस के लिए आदिवासी वर्ग का समर्थन सत्ता में वापसी की अनिवार्य शर्त जैसा है। पार्टी को 2018 में इसी वर्ग के समर्थन से बड़ी राजनीतिक ताकत मिली थी, लेकिन 2023 में वह उस प्रदर्शन को दोहरा नहीं सकी। अब कांग्रेस की कोशिश आदिवासी अधिकारों से जुड़े मुद्दों को फिर से राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाने की है। राहुल गांधी का बालाघाट में बैगा बच्चों की मौत के मामले के बाद आदिवासी समुदाय के बीच पहुंचना भी इसी रणनीति का हिस्सा माना गया। कांग्रेस जल-जंगल-जमीन, आदिवासी अधिकार, शिक्षा, आजीविका और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों के जरिए सरकार को घेरना चाहती है। पार्टी के सामने चुनौती यह है कि इन मुद्दों को केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित न रखकर आदिवासी क्षेत्रों में संगठनात्मक सक्रियता और भरोसे में कैसे बदला जाए। हाल ही में नई दिल्ली में हुई मध्य प्रदेश कांग्रेस की आदिवासी अधिकार, संरक्षण एवं सशक्तीकरण समिति की बैठक में भी इन्हीं विषयों पर चर्चा हुई। इसमें आदिवासी समुदाय के सामने मौजूद चुनौतियों और उनके अधिकारों की रक्षा के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका तथा समग्र विकास से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया गया।

डीएमएफ के 5 साल के बजट से बदलेगी गांवों-वार्डों की तस्वीर

खनिजों से खजाना भरने वाले 3 जिलों में अब विकास की नई खदान खोलेगी सरकार

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

मध्य प्रदेश के जिन जिलों की जमीन से निकलने वाले खनिजों ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती दी, अब उन्हीं जिलों की बदहाल बुनियादी सुविधाओं को सुधारने की तैयारी है। कोयला और दूसरे खनिजों के बड़े भंडार वाले सिंगरौली, शहडोल और अनूपपुर में सरकार अब विकास का नया मॉडल तैयार कर रही है। खनन से प्रभावित गांवों में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका जैसी जरूरतों को एक साथ लेकर पांच वर्षीय विकास योजना बनाई जाएगी। इसके लिए जिला खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) की राशि का उपयोग किया जाएगा। खास बात यह है कि अब तक डीएमएफ से कराए गए कार्यों की समीक्षा के साथ यह भी देखा जाएगा कि उन पर खर्च हुई राशि से जमीन पर कितना बदलाव आया। इसके लिए निजी एजेंसी की मदद ली जाएगी। गांवों और नगरीय वार्डों की जरूरतों का सर्वे कर उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति, उपलब्ध सुविधाओं और विकास की कमियों का आकलन होगा। इसके आधार पर पांच वर्षीय



पर्सपेक्टिव प्लान और सालाना एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि खनन से इन जिलों को राजस्व और औद्योगिक गतिविधियां तो मिलीं, लेकिन इसके साथ कई क्षेत्रों में विस्थापन, पर्यावरण प्रदूषण, पानी की समस्या, स्वास्थ्य संबंधी जोखिम और आजीविका पर असर भी पड़ा है। अब सरकार की कोशिश है कि खनिजों से मिलने वाली राशि का लाभ सीधे प्रभावित आबादी तक पहुंचे। प्रदेश के सभी 55 जिलों में डीएमएफ निधि के तहत करीब 3574.53 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं। इनमें से 10 खनिज प्रभावित जिलों सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, कटनी, बालाघाट, सतना, जबलपुर, छिंदवाड़ा, उमरिया और बैतूल के पास ही करीब 3147.10 करोड़ रुपए हैं। यानी प्रदेश की डीएमएफ निधि का बड़ा हिस्सा इन्हीं जिलों में केंद्रित है। डीएमएफ का गठन खनन से प्रभावित क्षेत्रों और वहां रहने वाले लोगों के हित में विकास कार्य कराने के उद्देश्य से किया गया है। खदानों के लीजधारकों को रॉयल्टी का 10 प्रतिशत हिस्सा डीएमएफ में जमा करना अनिवार्य है। इसी राशि से प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य कराए जाते हैं। हाल ही में नियमों में संशोधन के बाद डीएमएफ की 70 प्रतिशत राशि प्रभावित क्षेत्र में ही खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए पहले चरण में सबसे अधिक खनन प्रभावित सिंगरौली, शहडोल और अनूपपुर को चुना गया है। इसके बाद दूसरे जिलों में भी इसी तरह की योजनाएं तैयार की जाएंगी। पहले चरण की योजना का दायरा काफी बड़ा है। इसमें तीनों जिलों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। सिंगरौली में बैढन, चितरंगी और देवसर ब्लॉक की 316 ग्राम पंचायतें और 730 गांव शामिल होंगे। इसके अलावा तीन नगरीय निकायों के 75 वार्डों का भी विकास प्लान बनेगा। शहडोल में जयसिंहनगर, सोहागपुर, गोहपारू, ब्यौहारी और बुढ़ार ब्लॉक की 388 ग्राम पंचायतों के 859 गांवों को शामिल किया गया है। जिले के सात नगरीय निकायों के 142 वार्ड भी योजना का हिस्सा होंगे।

हमारे शिक्षक' ऐप का नियमित इस्तेमाल करने वालों को सम्मानित करेगा विभाग



■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

मध्य प्रदेश में ई-अटेंडेंस का विरोध कर रहे शिक्षकों के बीच स्कूल शिक्षा विभाग ने नियमित ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित करने की पहल की है। अब 'हमारे शिक्षक' ऐप का नियमित और सही तरीके से इस्तेमाल करने वाले शिक्षकों को विभाग डिजिटल प्रशस्ति पत्र देगा। इसमें समय पर ई-अटेंडेंस लगाने के साथ इसी ऐप के जरिए अवकाश आवेदन और अन्य विभागीय काम करने वाले शिक्षक शामिल होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. गोयल ने शुक्रवार को लोक शिक्षण संचालनालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने 'हमारे शिक्षक' ई-अटेंडेंस ऐप की उपलब्धियों पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि नियमित और समयबद्ध उपस्थिति दर्ज करने वाले शिक्षकों को ऐप के माध्यम से ही डिजिटल प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएं। सचिव डॉ. गोयल ने कहा कि शिक्षकों की नियमित उपस्थिति गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आधारशिला है। इससे स्कूलों में शिक्षण कार्य सुचारू और व्यवस्थित रहता है। साथ ही विद्यार्थियों में अनुशासन, समयबद्धता और पढ़ाई के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। उन्होंने कहा कि 'हमारे शिक्षक' ऐप का सार्थक उपयोग करने वाले शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देने की पहल से डिजिटल व्यवस्था मजबूत होगी।

भोपाल में अतिक्रमण के खिलाफ निगम की कार्रवाई, गुमटी और लोडिंग ऑटो जब्त

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

नगर निगम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में अवैध कब्जे हटाए। इस दौरान एक गुमटी और एक खराब लोडिंग ऑटो जब्त किया गया। निगम अमले ने अवैध चबूतरे, स्पीड ब्रेकर, दुकानों के बाहर रखे सामान, ठेले और फुटपाथ पर लगी सब्जी की दुकानों को भी हटवाया।

निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर शनिवार को अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने शहर के कोलार, कटियार मार्केट, सीआई कॉलोनी, राजहर्ष कॉलोनी, ललिता नगर, बंजारी चौराहा, अयोध्या बायपास, जेके रोड, 1100 क्वार्टर, एमपी नगर, माता मंदिर, लिंक रोड, पॉलीटेक्निक चौराहा, बाणगंगा,



वीआईपी रोड, लालघाटी और डीआईजी बंगला चौराहे सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान सीआई कॉलोनी में अशोका होटल के पीछे अवैध रूप से बनाया गया स्पीड ब्रेकर तोड़ा गया। कोलार की राजहर्ष कॉलोनी में मकान के सामने बना अवैध चबूतरा भी हटाया गया। कटियार मार्केट में तीन दुकानों के सामने लगाए गए टेंट हटवाए गए। वहीं वीआईपी रोड से लालघाटी, पॉलीटेक्निक से बाणगंगा और एमपी नगर से 1100 क्वार्टर तक खंभों पर लगे अवैध बोर्ड हटाए गए। माता मंदिर के सामने टायर पंचर की दुकान के बाहर रखे टायर भी हटवाए गए। इसके अलावा दुकानों के बाहर रखा सामान, फुटपाथ पर लगी सब्जी की दुकानें, ठेले, गुमठियां, काउंटर, कुर्सियां और टेबल सहित अन्य अतिक्रमण हटाए गए।

प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए एम्स भोपाल ने चलाया जागरूकता अभियान

बाकानिया के स्कूल और आंगनवाड़ी में शिक्षकों को दी जानकारी, शिकायत के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर 1800-180-3024

■ एक सत बुलेटिन, **नई दिल्ली।**

मेडिकल उपकरणों और जांच किटों के सुरक्षित उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एम्स भोपाल ने फंदा क्लस्टर के बाकानिया में विशेष अभियान चलाया। इसके तहत आंगनवाड़ी और शासकीय उच्चतर विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों, शिक्षकों और स्थानीय लोगों को मेडिकल उपकरणों से होने वाली प्रतिकूल घटनाओं तथा उनकी शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। सामुदायिक एवं पारिवारिक चिकित्सा विभाग के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें जूनियर मटेरियोविजिलेंस एसोसिएट आकाश



ठाकुर ने मेडिकल उपकरणों से होने वाली प्रतिकूल घटनाओं के साथ नियर-मिस घटनाओं के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि ऐसी घटनाओं की समय पर सूचना देना क्यों जरूरी है। लोगों को शिकायत दर्ज कराने के लिए एमवीपीआई की टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-180-3024, मोबाइल ऐप और उपभोक्ता रिपोर्टिंग फॉर्म की जानकारी दी गई। विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकों और विद्यार्थियों को भी जागरूक करते हुए कहा गया कि वे अपने परिवार के सदस्यों तक यह जानकारी पहुंचाएं। स्वास्थ्यकर्मी एमडीएई रिपोर्टिंग फॉर्म अथवा नजदीकी मेडिकल डिवाइस एडवर्स इवेंट मॉनिटरिंग सेंटर के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फार्माकोलॉजी विभाग की जूनियर रेजिडेंट डॉ. अतुल्या टीएच ने कहा कि प्रतिकूल घटनाओं की समय पर रिपोर्टिंग से मेडिकल उपकरणों की सुरक्षा निगरानी व्यवस्था मजबूत होती है। उल्लेखनीय है कि एम्स भोपाल का फार्माकोलॉजी विभाग भारत के मटेरियोविजिलेंस कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए मेडिकल डिवाइस एडवर्स इवेंट मॉनिटरिंग सेंटर एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने सुरक्षित दवाओं और मेडिकल उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने का संकल्प लिया।

गांवों में ही तैयार होंगे प्रमाणित बीज

पंचायत स्तर पर स्थापित होंगे 500 टन क्षमता के बीज प्रसंस्करण संयंत्र और गोदाम

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

किसानों को उच्च गुणवत्ता के प्रमाणित बीज स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई योजना शुरू की है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के बीज घटक के तहत अब ग्राम पंचायत स्तर पर आधुनिक बीज प्रसंस्करण संयंत्र और भंडारण गोदाम स्थापित किए जाएंगे। योजना के लिए 5 नवंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। योजना के तहत एक इकाई में 500 मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता का बीज प्रसंस्करण संयंत्र और 500 मीट्रिक टन क्षमता का भंडारण गोदाम बनाया जाएगा। इसकी कुल स्थापना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान सरकार देगी। अनुदान की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये प्रति इकाई तय की गई है। शेष राशि चयनित संस्था को स्वयं लगानी होगी। अनुदान का भुगतान काम की प्रगति के आधार पर तीन चरणों में किया जाएगा। पहली किस्त में 30 प्रतिशत यानी अधिकतम 12 लाख रुपये जिला कलेक्टर के साथ अनुबंध और लेआउट जमा करने के बाद मिलेंगे। दूसरी किस्त में 50 प्रतिशत यानी अधिकतम 20 लाख रुपये गोदाम निर्माण पूरा होने, अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट और मशीनरी ऑर्डर की प्रति देने पर जारी होंगे। अंतिम किस्त के रूप में 20 प्रतिशत यानी अधिकतम आठ लाख रुपये संयंत्र की स्थापना पूरी होने और जिला स्तरीय तकनीकी समिति से गुणवत्ता व भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र मिलने के बाद दिए



जाएंगे। योजना में इकाई की स्थापना के लिए समयसीमा भी तय की गई है। तीन महीने में 30 प्रतिशत, पांच महीने में 60 प्रतिशत और 12 महीने के भीतर पूरा काम करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय में काम पूरा नहीं करने पर अनुदान प्रभावित हो सकता है। दो साल का अनुभव जरूरी, मेरिट से होगा चयन योजना का लाभ लेने के लिए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और बहु-राज्य सहकारी समितियां पात्र होंगी। संबंधित संस्था के पास बीज उत्पादन का कम से कम दो साल का अनुभव होना जरूरी है। चयन के लिए 100 अंकों की मेरिट प्रणाली बनाई गई है। इसमें संस्था की अपनी भूमि, संबंधित पंचायत में गोदाम स्थापित करने की स्थिति, पहुंच मार्ग, बिजली की उपलब्धता, बीज उत्पादन का अनुभव और खरीफ व रबी दोनों सीजन में उत्पादन जैसे बिंदुओं को महत्व दिया जाएगा। इसके अलावा पिछले तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट और पोर्टल पर पंजीयन भी चयन का आधार होंगे। योजना से गांवों में ही बीज प्रसंस्करण और भंडारण की सुविधा विकसित होने की उम्मीद है। इससे किसानों को स्थानीय स्तर पर प्रमाणित बीज उपलब्ध हो सकेंगे और बीज उत्पादन से जुड़ी संस्थाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में कारोबार का अवसर मिलेगा। किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अब गांवों में ही प्रमाणित बीज तैयार करने की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बीज उत्पादन को बढ़ावा देकर किसानों को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। दूसरे क्षेत्रों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और गांवों में ही कृषि आधारित रोजगार के नए अवसर भी विकसित हो सकेंगे। गांवों में प्रमाणित बीज उत्पादन होने से किसानों को अपनी जरूरत के अनुसार बीज उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। ऐसे में स्थानीय स्तर पर बीज उत्पादन की व्यवस्था विकसित होने से यह समस्या कम हो सकती है।

संपादकीय

अधिक बच्चे दंडनीय नहीं

यदि आप दो से अधिक बच्चों के माता-पिता हैं, तो आपको किसी भी सरकारी तथा सामाजिक योजना से वंचित नहीं रखा जा सकता। आपको सरकारी सेवा अथवा नौकरी का भी लाभ मिलता रहेगा। आपको चुनाव लड़ने को भी अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता। बच्चों के प्रजनन और आपकी शारीरिक स्वायत्तता भी संविधान के अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकार के तौर पर दर्ज है। अब यह सर्वोच्च अदालत का भी फैसला है। अदालत की चिंता यह है कि देश की औसत प्रजनन दर 1.9 हो गई है। अर्थात माता-पिता औसतन 2 बच्चे भी पैदा नहीं कर रहे हैं। यह रिप्लेसमेंट लेवल (2.1) से भी कम है। यह लेवल वह दर है, जिस पर कोई आबादी बिना घटे ही खुद को बनाए रख सकती है। इस संदर्भ में सर्वोच्च अदालत का निर्णय है कि यदि किसी युगल के घर में 3 बच्चे हैं, तो माता-पिता में से किसी को भी दंडित नहीं किया जा सकता। दंडस्वरूप किसी भी सार्वजनिक लाभ, अवसर, परियोजना से वंचित भी नहीं रखा जा सकता। शीर्ष अदालत के सामने महाराष्ट्र के काकोड़ा ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच मंगला भीमराव का मामला था। जब मंगला के 3 बच्चे हुए, तब उन्हें चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दे दिया गया। शीर्ष अदालत ने उस अयोग्यता के फैसले को खारिज किया है। यही नहीं, सर्वोच्च अदालत के जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे ने इस मामले को एक उच्च पीठ के पास भी भेज दिया है। 2003 में हरियाणा उच्च न्यायालय ने 2 से अधिक संतान पैदा करने वालों को चुनाव लड़ने से वंचित करने के पक्ष में फैसला दिया था। अब उस फैसले पर सर्वोच्च अदालत में व्यापक पुनर्विचार होगा। बहरहाल भारत की आबादी में घटने के कोई भी रुझान या संकेत नहीं हैं, लेकिन बूढ़े, उम्रदराज लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है। जनगणना के मौजूदा आंकड़ों के आधार पर 2022-26 में भारत की उम्रदराज आबादी 15 करोड़ से अधिक होगी। 2036 तक यह संख्या करीब 22.7 करोड़ तक पहुंच सकती है। यह कुल आबादी का 15 फीसदी हिस्सा हो सकता है।

2047 तक विकसित भारत का सपना और संकल्प पूरा हो अथवा न हो, लेकिन 2050 तक भारत में बुजुर्गों की संख्या 32-34 करोड़ तक पहुंच सकती है। उस बिंदु के बाद हमारी जनसंख्या घटनी शुरू हो सकती है। फिलहाल हम विश्व के सबसे युवा देश हैं। गौरतलब यह है कि सरसंघचालक मोहन भागवत अधिक बच्चे पैदा करने का आह्वान करते रहे हैं। कुछ साधु-संत किस्म के चेहरे भी कम से कम 4 बच्चे पैदा करने की नसीहत देते रहे हैं। जैन मुनि तक अपने धर्म-अनुयायी भक्तों को अधिक बच्चों को जन्म देने का उपदेश देते रहे हैं, क्योंकि जैन समुदाय अत्यंत अल्पसंख्यक होता जा रहा है। इन आह्वानों और नसीहतों के सरोकार कुछ भी हों, लेकिन उनकी आड़ में सियासत भी जारी रही है। एक वर्ग जनसंख्या के असंतुलन के बयान देकर आरोप चस्पां करता रहा है कि एक खास समुदाय अधिक बच्चे पैदा कर रहा है, लिहाजा देश में आबादी के समीकरण बिल्कुल पलट सकते हैं। बहरहाल हम इन आरोपों को यहीं छोड़ते हैं और संवैधानिक मौलिक अधिकारों का विश्लेषण करते हैं। यदि आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दूसरे बच्चे के लिए 25,000 रुपए, तीसरे बच्चे पर 30,000 रुपए और चौथे बच्चे के लिए 40,000 रुपए नकद देने की हालिया घोषणा की है, तो बुनियादी चिंता यह है कि आंध्र में प्रजनन दर 2 से कम है। भारत में आंध्र के अलावा तमिलनाडु, केरल सरीखे दक्षिणी राज्यों की जनसंख्या अपेक्षाकृत घटी है। कारण कई हैं, जिनमें परिवार नियोजन भी प्रमुख है। वैसे हम अक्सर दो बच्चों वाली नीति का विरोध सुनते आए हैं और कई राज्यों ने इस नीति को स्वीकार करने या लागू करने से ही अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। ऐसे 15 राज्य हैं, जहां कोई भी नीति लागू नहीं है। आंध्र सरकार ने साल भर के मातृत्व अवकाश और दो माह के पितृत्व अवकाश की भी घोषणा की है। बहरहाल शीर्ष अदालत की चिंता समझनी चाहिए। देश में अब जनसंख्या-विस्फोट की स्थिति नहीं है, लिहाजा प्रजनन दर 1.9 हो गई है।

दीपावली महापर्व : धर्म, अध्यात्म और आर्थिक उन्नति का आधार



अभिषेक शर्मा



भारतवर्ष त्योहारों और सांस्कृतिक परंपराओं का देश है, जहां विविध धर्मों, संस्कृतियों और मान्यताओं की अनूठी झलक देखने को मिलती है। प्रत्येक पर्व अपने साथ कोई न कोई संदेश और सामाजिक सरोकार लेकर आता है, लेकिन दीपावली का महापर्व भारतीय जीवन में विशेष महत्व रखता है। यह केवल दीप जलाने और खुशियां मनाने का अवसर नहीं, बल्कि धर्म, अध्यात्म, सामाजिक समरसता और आर्थिक उन्नति का आधार भी है। भगवान श्रीराम के चौदह वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या आगमन की स्मृति से जुड़ा यह पर्व सत्य की असत्य पर और प्रकाश की अंधकार पर विजय का संदेश देता है। मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की आराधना के माध्यम से सुख, समृद्धि, बुद्धि और विवेक की कामना की जाती है। दीपावली हमें अपने भीतर के अंधकार, अहंकार और नकारात्मकता को समाप्त कर सद्भाव और सकारात्मकता अपनाने की प्रेरणा देती है। आर्थिक दृष्टि से भी दीपावली देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान करती है। बाजारों में बढ़ती रौनक, खरीदारी और व्यापारिक गतिविधियों से छोटे-बड़े व्यापारियों, कारीगरों, श्रमिकों, कुम्हारों और स्थानीय उत्पादकों को रोजगार एवं आय के अवसर मिलते हैं। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना स्थानीय व्यापार और आत्मनिर्भरता को मजबूती देने का माध्यम बन सकता है। आज आवश्यकता है कि दीपावली को केवल दिखावे और आतिशबाजी तक सीमित न रखें, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सद्भाव और जरूरतमंदों की सहायता को भी उत्सव का हिस्सा बनाएं। दीपावली का वास्तविक अर्थ तभी सार्थक होगा, जब हर घर में खुशहाली, हर हाथ को रोजगार और समाज के प्रत्येक वर्ग के जीवन में समृद्धि का प्रकाश पहुंचे। यही इस महापर्व का वास्तविक संदेश है।

पर्यटन बाजार की खोज

पर्यटन संभावनाओं के अक्स में अब होटल एसोसिएशनें समूचे देश से अपने हिस्से का व्यवसाय खोज रही हैं, तो यह स्थायी रूप से प्रगतिशील कदम माना जाएगा। बेशक पिछले कई दशकों में हिमाचल का पर्यटन निवेश अब अपनी क्षमता के जोखिम से इतना बड़ा नजर आता है कि साल के कई भाग सूखे निकल जाते हैं। कहना न होगा कि टूरिस्ट आगमन पूरे साल की क्षमता में एक तरह का उतार चढ़ाव है। कभी अटल टनल से एक ही दिन में बीस हजार वाहन गुजर जाते हैं, तो कभी मनाली की राहें सूनी पड़ जाती हैं। इसी तरह की उदासियों से रूबरू हिमाचल के कमोबेश सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन अपने-अपने पर्यटन कैलेंडर को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन पर्यटन केवल होटल व्यवसाय नहीं, बल्कि पर्यटन व्यापार है जो विविध गतिविधियों के केंद्र में हुजूम बनाता है।

होटल संघों के अलावा हिमाचल के व्यापार मंडलों, टैक्सी आपरेटरों, स्थानीय निकायों तथा रेहड़ी-फड़ी वालों के साथ मिल कर ही पर्यटन बाजार की परिभाषा को सुदृढ़ करने की जरूरत है। प्रदेश के पर्यटन सीजन को बारह महीने बांटने की कोशिश में नए डेस्टिनेशन, नए इवेंट, नए उपचार और नए पार्टनर खोजने होंगे। इसी तरह की एक कोशिश करते हुए धर्मशाला की स्मार्ट सिटी होटल एवं रेस्तरां एसोसिएशन तथा भद्रवाह टूरिज्म एसोसिएशन के बीच एक संयुक्त प्रयास शुरू हुआ है। दोनों एसोसिएशन एक सर्किट के तहत दो डेस्टिनेशन के बीच सामंजस्य, संपूर्णता, आकर्षण, विविधता तथा सहूलियत जोड़ रही हैं, तो यह अभिनव प्रयोग हिमाचल के कई अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ भी हो सकता है।

यह गठजोड़ हिमाचल पथ परिवहन निगम के साथ पड़ोसी राज्यों की परिवहन व्यवस्था से जुड़ कर उत्तर भारत के कई टूरिस्ट सर्किटों को बुलंदी दे सकता है। मसलन हिमाचल से हरिद्वार के लिए कम से कम सौ रूट संचालित होते हैं, लेकिन दोनों राज्यों के बीच अलग-अलग टूरिस्ट सर्किट बनाने के गंभीर प्रयास नहीं हुए। जो टूरिस्ट देवी दर्शन के लिए हिमाचल के मंदिरों में आता है, हम उसके लिए धार्मिक सर्किट नहीं बना पाए। उदाहरण के लिए ज्वालाजी आने वाले पर्यटक को नादौन की ध्यानूं समाधि आज भी मीलों दूर है। हम हाई एंड टूरिस्ट की बात करते हैं, लेकिन हाई एंड टूरिस्ट सर्किट नहीं बना पाए। यानी कि ट्राइबल, सांस्कृतिक और धरोहर के अलावा साहसिक पर्यटन को सर्किट के हिसाब से हाई एंड टूरिस्ट के काबिल नहीं बना पाए। शिमला आज हाई एंड के बजाय शोरगुल पर्यटन का हिस्सा बन गया, तो हमारी योजनाओं का कसूर है। हिमाचल को अपने सीमांत क्षेत्रों पर नए पर्यटक सर्किट बना कर भीड़ में भटकते पर्यटक को आसरा देना चाहिए। मसलन पौंग और कौल डैम के अलावा भाखड़ा व अन्य झीलों के किनारे पर्यटक मेले लगा कर एक वर्ग को संतुष्ट किया जा सकता है।

आडवाणी जी: एक शताब्दी की ओर बढ़ती प्रेरणादायी यात्रा

नरेंद्र मोदी (प्रधानमंत्री)

आज 8 नवंबर को श्री लालकृष्ण आडवाणी जी अपने जीवन के सौवें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। ये कितना सुखद संयोग है कि आज ही दीपावली का पावन पर्व भी है। प्रभु श्रीराम और दीपों के इस उत्सव के साथ आडवाणी जी के जीवन का इतना महत्वपूर्ण पड़ाव जुड़ना, इस अवसर को और भी यादगार बनाता है। इस संयोग को एक और बात विशेष बनाती है। इसी वर्ष हम जनसंघ की स्थापना के 75 वर्ष, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती भी मना रहे हैं।

आज का ये अवसर मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत भावुक कर देने वाला है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे हमेशा आडवाणी जी का स्नेह, सान्निध्य और मार्गदर्शन मिलता रहा है। आज उनके साथ बिताए हुए अनगिनत पल, उनसे जुड़ी कितनी ही स्मृतियां मन में उमड़ रही हैं।

सार्वजनिक जीवन में काम करते हुए कई दशक पहले मुझे उनके संपर्क में आने का अवसर मिला था। धीरे-धीरे हमारा ये संबंध इतना आत्मीय हो गया कि वे मेरे लिए अभिभावक की तरह बन गए। उन्होंने मेरा हाथ थामकर मुझे राजनीति की बारीकियां सिखाईं, कदम-कदम पर मेरा मार्गदर्शन किया। जीवन में जब भी कोई कठिन परिस्थिति आई, उनका अनुभव और उनकी सीख मेरे लिए संबल बने। उनकी वैचारिक स्पष्टता, उनका आत्मविश्वास और अपने सिद्धांतों के प्रति उनकी अटूट निष्ठा ने मुझे हमेशा प्रेरित किया। आज भी जब मैं उनसे मिलने जाता हूं, तो उनके साथ बिताया हुआ समय मुझे नई ऊर्जा और नई प्रेरणा से भर देता है। आज इस अवसर पर श्रद्धेय आडवाणी जी के लिए मन में एक ही भाव उमड़ रहा है...

जीवेत शरदः शतं, पश्येम शरदः शतं, शृणुयाम शरदः शतं।

ऐसे व्यक्तित्व बहुत कम हैं, जिनके जीवन में आधुनिक भारत के इतिहास के इतने सारे अध्याय समाए हों। आडवाणी जी का जन्म 8 नवंबर, 1927 को देव दीपावली के दिन हुआ था। 1947 में, जब वे युवा थे, तब उन्हें विभाजन की पीड़ा सहनी पड़ी। सिंध में अपना घर, अपना परिवेश, अपनी जानी-पहचानी दुनिया छोड़कर उन्हें आना पड़ा। सब कुछ पीछे छूट गया और जीवन की नई शुरूआत शून्य से करनी पड़ी। लेकिन इस कठिन अनुभव को लेकर उनके मन में कभी कोई कड़वाहट या पछतावा नहीं रहा।

कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हों, नए सिरे से कुछ खड़ा करने का उनका ये संकल्प जीवनभर उनके साथ रहा। जनसंघ को मजबूत बनाने और बाद में भारतीय जनता पार्टी के निर्माण में भी उनका यही गुण सामने आया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल में देश की राजनीति ने बड़े बदलाव देखे। 1989 में कांग्रेस की सीटें 400 से घटकर 200 से भी नीचे आ गईं। 1996 में भाजपा पहली बार देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। आडवाणी जी ने कार्यकर्ताओं की अनेक पीढ़ियों को तैयार किया। उन्होंने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर पार्टी की मजबूत नींव रखी। यहां मैं आडवाणी जी के व्यक्तित्व की दो ऐसी विशेषताओं का उल्लेख करना चाहूंगा, जो एक नेता के रूप में उन्हें अलग पहचान देती हैं। पहली है, उनकी वैचारिक स्पष्टता और बौद्धिक प्रखरता। उनके भाषणों और लेखन में इसकी झलक साफ दिखाई देती थी। जनसंघ और भाजपा के लिए उन्होंने जो प्रस्ताव लिखे, वे आज भी पढ़ने और समझने योग्य हैं। उनके इंटरव्यू में भी विचारों की गहराई के साथ शब्दों की स्पष्टता और सटीकता दिखाई देती थी। दूसरी विशेषता थी, भारतीय राजनीति में लंबे समय तक हावी रही छद्म धर्मनिरपेक्षता को लेकर उनका स्पष्ट और निर्भीक रुख। उन्होंने देश के राजनीतिक विमर्श में इस प्रवृत्ति की वास्तविकता को उजागर किया।

आडवाणी जी को जो भी जिम्मेदारी मिली, उन्होंने उसे पूरी निष्ठा और लगन से निभाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने सबसे पहले राजस्थान के अलग-अलग क्षेत्रों में काम किया। इसके बाद वे दिल्ली आए, जहां उन्हें अटल जी के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिला। इसके बाद की कहानी तो इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। दोनों ने दशकों तक कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। आडवाणी जी के लिए अटल जी हमेशा उनके नेता और मार्गदर्शक रहे।



राजनीति के इतिहास में ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, जब दो बड़े कद के नेता इतने लंबे समय तक एक-दूसरे के साथ खड़े रहे हों। अक्सर समय के साथ राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं, महत्वाकांक्षाएं टकराती हैं और साथ चलने वाले नेता भी अलग-अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। लेकिन अटल जी और आडवाणी जी का साथ अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। इतिहास साक्षी है, पांच-छह दशकों की इस लंबी यात्रा में दोनों एक-दूसरे के सहयोगी बने रहे। एक-दूसरे के प्रति उनका विश्वास और सम्मान हमेशा बना रहा। अटल जी के जीवन के अंतिम समय तक ये साथ कायम रहा। भारतीय राजनीति में आपसी विश्वास, सहयोग और समर्पण की ये परंपरा आज भी एक बड़ी प्रेरणा है। आडवाणी जी जब दिल्ली आए थे, तब ये शहर विभाजन की विभीषिका से उबरने का प्रयास कर रहा था। ऐसे समय में उन्होंने जनसंघ को मजबूत बनाने के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। 1967 में वे दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष बने। इस दौरान उन्होंने स्वर्गीय विजय कुमार मल्होत्रा जी के साथ मिलकर काम किया, जो मुख्य कार्यकारी पार्षद बने थे।

एक सांसद के रूप में आडवाणी जी की यात्रा 1970 के दशक से शुरू हुई। संसद में उनकी सक्रिय भागीदारी की आज भी सराहना होती है। एक सांसद के रूप में, दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के रूप में और सत्ता पक्ष में रहते हुए भी उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। संसदीय जिम्मेदारियों में व्यस्त रहने के बावजूद वे लगातार देश के अलग-अलग हिस्सों में जाते रहे, लोगों से मिलते रहे और उनसे संवाद करते रहे।

1991 के लोकसभा चुनाव की स्मृतियां आज भी मेरे मन में ताजा हैं। उस समय तय हुआ था कि आडवाणी जी दो लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे। इनमें से एक सीट गांधीनगर की थी। आडवाणी जी का गुजरात से बहुत पुराना नाता रहा है। विभाजन के बाद उनके पिताजी कच्छ में आकर बसे थे। 1976 में, जब देश में आपातकाल अपने चरम पर था, तब आडवाणी जी गुजरात से राज्यसभा सांसद भी बने थे। इस तरह 1991 में गांधीनगर से चुनाव लड़ना उनके लिए एक तरह से घर वापसी जैसा था।

उस समय मैं भाजपा के संगठन में काम कर रहा था। मुझे आडवाणी जी के नामांकन पत्र तैयार करने से लेकर पूरे चुनाव अभियान में उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला। गांधीनगर की जनता ने भी उन्हें बार-बार बड़े बहुमत से विजयी बनाकर संसद भेजा। मेरे लिए ये भी बहुत सौभाग्य की बात रही कि गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र का मतदाता होने के नाते मुझे अनेक बार आडवाणी जी को अपना वोट देने का अवसर मिला। अपने संसदीय क्षेत्र और वहां के लोगों के प्रति उनका लगाव, उनकी चिंता और उनकी जरूरतों का ध्यान रखने का उनका भाव, हम सभी के लिए सीखने योग्य है।

आपातकाल आडवाणी जी के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उस दौर में वे लोकतंत्र को बचाने और संविधान की रक्षा के संघर्ष में अग्रिम पंक्ति में खड़े रहे। आपातकाल के दौरान उन्होंने जो कुछ देखा, अनुभव किया और महसूस किया, उसकी झलक उनकी पुस्तक ह्यअ ढ१२ङ्बल्ली१'२ रू१'स्र-इङ्बङ्ब'ह्ल में भी मिलती है। इस पुस्तक का एक हिस्सा है–ह्यअ ळं'ी ङ्बा ळ६ङ्ब ऐीशैल्लीू२ह्ल। इसमें उन्होंने जून 1975 से भारत में शुरू हुई घटनाओं और 1933 में हिटलर के शासन के दौरान जर्मनी में हुई घटनाओं के बीच आश्चर्यजनक समानताओं का बहुत प्रभावी ढंग से वर्णन किया है।

आडवाणी जी विपक्ष में जितने प्रखर नेता रहे, प्रशासन में भी उतने ही कुशल साबित हुए। 1977 में जब जनता सरकार बनी, तो उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। इस मंत्रालय में उनके कार्यकाल को आज भी विशेष रूप से प्रभावशाली माना जाता है। बाद में उप प्रधानमंत्री और देश में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गृह मंत्रियों में से एक के रूप में उन्होंने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे सुरक्षा बलों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए, उन्हें आज भी बड़े आदर और आत्मीयता से याद किया जाता है। आतंकवाद के खिलाफ उनका रुख हमेशा स्पष्ट और दृढ़ रहा। उनके इसी संकल्प के कारण देश को आतंकवाद से निपटने के लिए एक सख्त कानून मिला।

सोमनाथ से अयोध्या तक की रथयात्रा आडवाणी जी के जीवन का एक ऐतिहासिक अध्याय है। इस यात्रा ने भारतीय समाज को एक नई और सकारात्मक दिशा दी। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इस ऐतिहासिक यात्रा से जुड़ने का अवसर मिला। यात्रा की परिकल्पना से लेकर उसकी तैयारियों और फिर उसे आगे बढ़ाने तक, मुझे हर चरण में योगदान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रथयात्रा के शुभारंभ के समय सोमनाथ में उपस्थित रहना भी मेरे लिए एक अविस्मरणीय अनुभव था। इतनी लंबी यात्रा अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। लगातार सफर, लंबे समय तक काम करना, शारीरिक थकान और इन सबके बीच अपने उद्देश्य पर पूरी तरह केंद्रित रहना, इसके लिए अद्भुत धैर्य और सहनशक्ति की आवश्यकता होती है। आडवाणी जी ने इस पूरी यात्रा में जिस जीवटता और संकल्पशक्ति का परिचय दिया, वो अपने आप में प्रेरणादायी है।

इस यात्रा से जुड़ा एक प्रसंग आज भी मेरी स्मृतियों में ताजा है। बिहार में आडवाणी जी की गिरफ्तारी हम सभी के लिए बहुत दुखद क्षण था। उस समय गुजरात में भाजपा ने चिमनभाई पटेल की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके पीछे संदेश बिल्कुल स्पष्ट था...अपनी विचारधारा और राम मंदिर के निर्माण के संकल्प पर कोई समझौता नहीं होगा। हमारे अनेक वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शपथ ली कि चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होकर ही रहेगा। और फिर वर्षों बाद वो ऐतिहासिक अवसर भी आया, जब जनता-जनार्दन के आशीर्वाद से अयोध्या में प्रभु श्रीराम का भव्य मंदिर का सपना साकार हुआ। आडवाणी जी के व्यक्तित्व के ऐसे अनेक पहलू हैं, जो उन्हें और भी विशिष्ट बनाते हैं। उनकी सादगी और सरलता भी ऐसी ही एक विशेषता है। नवनिर्माण आंदोलन के बाद आडवाणी जी जूनागढ़ आए थे। वहां वे एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह पूरे एक महीने तक रहे और विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी को तैयार करने में जुटे रहे। इन चुनावों में जनता ने इंदिरा गांधी की कांग्रेस को नकार दिया था।

आडवाणी जी ने अपने आचरण से हमेशा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और शुचिता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक है। जो लोग उनके साथ रहे हैं, वे जानते हैं कि वे अखबारों को भी कितने ध्यान से और कितनी बारीकी से पढ़ते रहे हैं। सिनेमा और रंगमंच से भी उनका गहरा लगाव रहा है। वर्षों तक वे बड़े उत्साह से फिल्मों की समीक्षा भी करते रहे हैं। इतिहास के प्रति उनकी गहरी समझ और उसे सहेजकर रखने की उनकी भावना भी उल्लेखनीय है। उनकी पुस्तक ह्यट८ उङ्ब४ल्ल३१८ ट८ छीह्ल में इसकी सुंदर झलक मिलती है।

आडवाणी जी का अपनी सिंधी संस्कृति से हमेशा गहरा जुड़ाव रहा है। लेह के पास सिंधु दर्शन पूजा को लोकप्रिय बनाने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुझे स्वयं भी एक बार आडवाणी जी और जॉर्ज फर्नांडिस जी के साथ सिंधु दर्शन पूजा में शामिल होने का सौभाग्य मिला था। आडवाणी जी की इस असाधारण जीवन यात्रा की बात हो और कमला आडवाणी जी का उल्लेख न हो, तो ये यात्रा अधूरी रह जाएगी। इतने लंबे सार्वजनिक जीवन में कमला जी हमेशा उनकी शक्ति और संबल बनी रहीं। हर कदम पर उनका साथ दिया। कराची में पले-बढ़े आडवाणी जी ने शायद ही कभी कल्पना की होगी कि जीवन उन्हें कितनी लंबी और असाधारण यात्रा पर ले जाएगा। देश के प्रति उनके योगदान के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने वर्ष 2024 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया।

आज जब आडवाणी जी अपने जीवन के सौवें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो मैं ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूं। वे इसी तरह हम सभी को प्रेरणा देते रहें, हमारा मार्गदर्शन करते रहें।

न्यूज ब्रीफ

बोरियों में भरकर ग्वालियर लाई गई 111 किलो मिलावटी मिठाई जब्त

ग्वालियर। त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिलावटखोरों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। मिलावट की गुप्त शिकायत के आधार पर विभाग की टीम ने हनुमान चौराहा स्थित प्रसिद्ध 'साई कृपा स्वीट्स' (बालाजी स्वीट्स) के प्रतिष्ठान और उससे संबद्ध डेयरी पर अचानक छापा मारा। इस कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके से 111 किलोग्राम संदिग्ध मिठाई जब्त की। जांच में सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि ये मिठाइयां मुरैना में तैयार की गई थीं और फिर बोरियों में भरकर ग्वालियर बिक्री के लिए लाई गई थीं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मिठाइयों के सैंपल सील कर जांच प्रयोगशाला भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा डेयरी परिसर की सघन तलाशी के दौरान 48 किलोग्राम मिल्क केक, 48 किलोग्राम मलाई बर्फी और 15 किलोग्राम सोहनपापड़ी का बड़ा भंडार बरामद किया गया। यह खाद्य सामग्री बेहद अमानक तरीके से रखी गई थी; मिल्क केक और मलाई बर्फी दो-दो छोटी बोरियों (कट्टों) में भरी हुई पाई गई, जबकि सोहनपापड़ी को भी एक कट्टे में भरकर रखा गया था। टीम ने तीनों मिठाइयों के नमूने (सैंपल) एकत्रित कर पूरी खेप को तत्काल प्रभाव से जब्त कर लिया।

फर्जी दस्तावेज से बने 31 बांग्लादेशियों के पासपोर्ट निरस्त, 66 आरोपी फरार

ग्वालियर। मध्य प्रदेश में फर्जी दस्तावेजों और पहचान के आधार पर भारतीय पासपोर्ट हासिल करने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ विशेष कार्य बल (एसटीएफ) और पासपोर्ट विभाग ने बड़ी व सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। एसटीएफ द्वारा सौंपी गई विस्तृत जांच रिपोर्ट के आधार पर भोपाल स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने कुल 70 संदिग्ध पासपोर्टों में से 31 पासपोर्ट तत्काल प्रभाव से निरस्त (रद्द) कर दिए हैं। जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि निरस्त किए गए पासपोर्टों में से 17 पासपोर्ट अकेले ग्वालियर जिले के डबरा तहसील स्थित सिमरिया गांव के पते पर जारी कराए गए थे। विभाग के अधिकारियों के अनुसार, शेष बचे फर्जी पासपोर्टों को भी निरस्त करने की विधिक प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इस बड़े फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद जांच एजेंसियों ने जब आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश की, तो पता चला कि मामले में नामजद 66 आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं। एसटीएफ की गहन पड़ताल में यह बात स्पष्ट हुई है कि इन बांग्लादेशी नागरिकों ने स्थानीय स्तर पर साठगांठ करके अपने नाम, उम्र और पहचान बदलकर फर्जी भारतीय नागरिकता के दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी व निवास प्रमाण पत्र) तैयार करवाए थे। इन्हीं कूटरचित दस्तावेजों के इस्तेमाल से उन्होंने ग्वालियर और आसपास के जिलों के पतों पर पासपोर्ट बनवाए।

पर्यावरण संरक्षण के लिए नेपाल से निकली पद्मभूषण डॉ. अनिल जोशी की साइकिल यात्रा आज ग्वालियर में

ग्वालियर। प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनमानस में जागरूकता फैलाने के पावन उद्देश्य से नेपाल के जनकपुर से रवाना हुई अंतरराष्ट्रीय साइकिल यात्रा शनिवार, सात नवंबर को ग्वालियर पहुंचेगी। पद्मभूषण डॉ. अनिल प्रकाश जोशी के सशक्त नेतृत्व में 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) को जनकपुर से शुरू हुई इस यात्रा में कुल 14 साइकिल यात्री शामिल हैं, जो लगातार पैडल मारकर पर्यावरण चेतना का संदेश फैला रहे हैं। यह साइकिल यात्रा डबरा के रास्ते ग्वालियर शहर की सीमा में प्रवेश करेगी। यात्रा दल के सदस्य शनिवार सुबह लगभग 11:00 बजे आईटीएम यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे। इसके पश्चात, सुबह 11:30 बजे विश्वविद्यालय परिसर में एक विशेष संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस संवाद में साइकिल यात्री विद्यार्थियों के साथ अपने अब तक के अनुभवों को साझा करेंगे और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर विस्तृत चर्चा करेंगे। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद यह यात्रा अपने अगले पड़ाव धौलपुर (राजस्थान) के लिए रवाना हो जाएगी। लगभग 50 से 55 दिनों की अवधि वाली यह वृहद यात्रा कुल 3,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यह साइकिल यात्रा नेपाल से शुरू होकर भारत के सात प्रमुख राज्यों से गुजर रही है, जिनमें झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड शामिल हैं। यात्रा का मुख्य ध्येय समाज को प्रकृति और पर्यावरण के अमूल्य महत्व से पुनः जोड़ना है। इसके संरक्षण के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना करना भी असंभव है।

नियुक्ति में इस्तेमाल दस्तावेजों की प्रमाणिकता साबित करना कर्मचारी की भी जिम्मेदारी

फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाने के मामले में कर्मचारी को हाई कोर्ट से झटका

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल करने के आरोप से जुड़े मामले में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने संबंधित कर्मचारी को बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट की युगलपीठ ने कर्मचारी डॉक्टर गिरजा शंकर गुप्ता की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान अदालत ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि नियुक्ति हासिल करने के लिए जिन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया है, उनकी प्रामाणिकता साबित करने की जिम्मेदारी संबंधित कर्मचारी की भी है। केवल दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने की बात कहकर विभागीय जांच को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जा सकता। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र यादव की युगलपीठ ने की। याचिकाकर्ता ने 22 अक्टूबर 2026 को पारित आदेश के एक हिस्से को चुनौती देते हुए पुनर्विचार याचिका दायर की थी। उसका कहना था कि विभागीय जांच से संबंधित सभी दस्तावेज उसे उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जबकि हाई कोर्ट के पूर्व आदेश में दस्तावेज उपलब्ध कराने का उल्लेख किया गया है। इसी आधार पर उसने आदेश के संबंधित हिस्से पर पुनर्विचार करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में तर्क दिया गया कि विभागीय जांच में अपना पक्ष रखने के लिए उसे जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता है। उसका कहना था कि मांगे गए सभी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए, जिसके कारण वह अपना बचाव प्रभावी तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है। याचिकाकर्ता ने इसी आधार पर पूर्व में पारित आदेश के एक हिस्से को संशोधित करने की मांग की थी। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने विभागीय रिकॉर्ड का परीक्षण किया। अदालत के सामने आया कि विभाग ने 4 दिसंबर 2025 को पत्र जारी कर आरोपों का विवरण और उनसे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने की जानकारी दी थी। इसके बाद कर्मचारी ने 10 दिसंबर को कुछ अन्य दस्तावेजों की मांग की थी। युगलपीठ ने दोनों पक्षों के तथ्यों और रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद पाया कि कर्मचारी द्वारा मांगे गए अतिरिक्त दस्तावेजों का विभागीय जांच के मुख्य मुद्दे से कोई सीधा संबंध नहीं था। अदालत ने माना कि ऐसे दस्तावेजों की मांग के आधार पर जांच की प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से लंबित रखने का प्रयास किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने स्पष्ट किया कि जिस आधार और दस्तावेजों के जरिए किसी व्यक्ति ने नौकरी प्राप्त की है, उनकी प्रामाणिकता साबित करना संबंधित कर्मचारी की भी जिम्मेदारी है। विभागीय जांच में केवल अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग करते रहना पर्याप्त नहीं है।

आरएसएस का शताब्दी संकल्प शिविर 4 दिसंबर से, दत्तात्रेय होसबाले देंगे युवाओं को मार्गदर्शन



एक सत बुलेटिन, ग्वालियर

आरएसएस के मध्यभारत प्रांत द्वारा एक ऐतिहासिक और भव्य आयोजन की रूपरेखा तैयार की गई है। संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आगामी चार से छह दिसंबर तक ग्वालियर के प्रसिद्ध मेला मैदान में विशाल 'शताब्दी संकल्प शिविर' का आयोजन किया जाएगा। इस त्रिदिवसीय शिविर में मध्यभारत प्रांत के अंतर्गत आने वाले सभी 31 जिलों से लगभग तीन हजार महाविद्यालयीन छात्र और युवा सहभागी के रूप में शामिल होंगे। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का मिलेगा मार्गदर्शन इस तीन दिवसीय भव्य आयोजन के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले की विशेष उपस्थिति रहने की पूरी संभावना है, जहां वे शिविरार्थियों को संबोधित करेंगे। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रबोध, सामाजिक समरसता, नागरिक कर्तव्यों और संगठनात्मक जीवन मूल्यों के प्रति गहरी समझ विकसित करना है। इसके माध्यम से महाविद्यालयीन छात्रों को देश निर्माण और सामाजिक चेतना के कार्यों से जोड़ने पर विशेष बल दिया जाएगा। कुंभ की तर्ज पर बनाई जाएगी विशाल टेंट सिटी शिविर के सुचारू संचालन और प्रतिभागियों के प्रवास के लिए ग्वालियर के मेला मैदान में तैयारियां जोर-शोर से शुरू कर दी गई हैं। आयोजन स्थल पर प्रयागराज कुंभ की तर्ज पर एक भव्य और सुव्यवस्थित टेंट सिटी बसाई जा रही है, जिसमें तीन हजार से अधिक विद्यार्थियों के रहने, भोजन और अन्य दैनिक आवश्यकताओं की व्यवस्था रहेगी। भूमि पूजन का कार्य संपन्न होने के साथ ही तैयारियों का औपचारिक शुभारंभ कर दिया गया है और वर्तमान में मैदान के समतलीकरण तथा बुनियादी ढांचे को खड़ा करने का कार्य तेजी से चल रहा है। व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिभागियों का पंजीयन जिला स्तर पर पूरा किया जाएगा।

धनतेरस पर जबरदस्त खरीदारी, बाजारों में खूब हुई धनवर्षा, 700 करोड़ रुपये का हुआ बंपर कारोबार

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



प्रकाश के पर्व दीपावली के पहले दिन धनतेरस पर ग्वालियर का समूचा बाजार ग्राहकों की भारी भीड़ से सराबोर नजर आया और सर्राफा से लेकर ऑटोमोबाइल तक झूमकर धन की वर्षा हुई। सुबह से ही शुरू हुआ ग्राहकों की आवाजाही का सिलसिला दोपहर होते-होते जनसैलाब में तब्दील हो गया। शाम ढलते ही शहर के प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों जैसे महाराज बाड़ा, सराफा बाजार, लश्कर, नई सड़क, जयेंद्रगंज और सिटी सेंटर के बाजारों में तिल रखने तक की जगह नहीं बची। बड़े-बड़े ब्रांडेड शोरूम्स से लेकर पटरी की दुकानों तक हर जगह लोग अपनी पसंद के अनुसार आभूषण, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान, बर्तन और पूजा के सामान की खरीदारी करते दिखे। बाजार विश्लेषकों और प्रमुख व्यापारी संगठनों के शुरुआती आकलन के मुताबिक इस बार धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर शहर में लगभग 500 से 700 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड कारोबार दर्ज किया गया है। ज्वेलरी शोरूम्स में जहां सोने-चांदी के सिक्कों, गिन्नियों और नए डिजाइनों की जमकर बिक्री हुई, वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी नए दोपहिया और चार पहिया वाहनों की डिलीवरी लेने के लिए ग्राहकों की लंबी कतारें देखी गईं। इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में ढाई गुना उछाल, डिस्काउंट ऑफर्स का उठाया लाभ इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज के शोरूम्स पर सुबह से ही खरीदारों की खासी चहल-पहल रही। ग्राहकों ने टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, स्मार्ट मोबाइल फोन, लैपटॉप और ओवन जैसे घरेलू उपकरणों की जमकर खरीदारी की। कंपनियों और स्थानीय डीलरों द्वारा दी जा रही विशेष छूट, कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर्स का लाभ उठाने के लिए लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। व्यापारियों का अनुमान है कि इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में पिछले वर्ष की तुलना में करीब 2.5 गुना अधिक व्यापार हुआ है।

बथेस्डा इंस्टीट्यूट में मतांतरण की शिकायत पर जांच शुरू, आयोजन को लेकर पुलिस-प्रशासन सख्त

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



मुरार वृत्त के अंतर्गत आने वाले बिजौली थाना क्षेत्र स्थित बथेस्डा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित वार्षिक समारोह के दौरान मुख्यमंत्री से मतांतरण की कथित शिकायत किए जाने के मामले में पुलिस प्रशासन ने गहन जाँच-पड़ताल आरंभ कर दी है। इसी क्रम में शुक्रवार को बिजौली थाने की पुलिस बल ने घटनास्थल पर पहुँचकर वस्तुस्थिति का जायजा लिया। मौके पर पंचनामा तैयार करने के साथ-साथ कार्यक्रम से जुड़े फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफी को भी साक्ष्य के रूप में सुरक्षित कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों को इस प्रकरण में उच्च स्तर से विधिवत जाँच के निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके चलते खुफिया तंत्र भी पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इस संवेदनशील मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए लोगों के बयान भी दर्ज करेगी। जाँच के दौरान जब पुलिस ने आयोजकों से इस वृहद आयोजन के वास्ते प्रशासनिक अनुमति से जुड़े दस्तावेज मांगे, तो उन्होंने उच्च न्यायालय की अनुमति होने का दावा किया। हालांकि, पुलिस द्वारा लिखित आदेश प्रस्तुत करने को कहे जाने पर आयोजक कोई वैध कागजात या आदेश उपलब्ध नहीं करा सके। प्राप्त शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि उक्त वार्षिक आयोजन की आड़ में दलितों और आदिवासियों का मतांतरण (धर्मांतरण) कराया जा रहा है तथा यह कृत्य प्रत्येक वर्ष दोहराया जाता है। पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों और साक्ष्यों की विस्तृत जाँच-पड़ताल के पश्चात ही इस मामले में वास्तविक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।

त्योहारी खरीदारी के बीच साइबर ठगी का खतरा, ग्वालियर पुलिस ने दी चेतावनी

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



दीपावली के पावन पर्व के नजदीक आते ही बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। परिधानों, आभूषणों, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और उपहारों की चल रही इस जमघट के बीच साइबर ठग भी खासे सक्रिय हो गए हैं। त्योहारी उल्लास और खरीदारी की जल्दबाजी का अनुचित लाभ उठाकर ठग लोगों को अपना शिकार बनाने के नए-नए तौर-तरीके अपना रहे हैं। इसे देखते हुए ग्वालियर पुलिस ने नागरिकों के लिए एक विशेष एडवाइजरी जारी कर अत्यधिक सावधानी बरतने का आह्वान किया है। एपीके फाइल और लुभावने संदेशों से रहें सतर्क पुलिस प्रशासन के अनुसार, आकर्षक ऑफर्स, डिस्काउंट कूपन और पर्वतीय शुभकामना संदेशों की आड़ में भेजी जाने वाली एपीके फाइलों के माध्यम से मोबाइल फोन को हैक किया जा सकता है। इन मैलवेयर फाइलों के जरिए ठग आसानी से बैंक खातों तक पहुँच बनाकर पूरी रकम साफ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, त्यौहार के इन दिनों में बैंकों में लगातार अवकाश होने के कारण वित्तीय धोखाधड़ी होने की स्थिति में बैंक खाते को तुरंत फ्रीज या ब्लॉक करवाना भी एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अज्ञात लिंक या संदिग्ध एपीके फाइल को डाउनलोड करने से बचें और पूरी तरह सतर्कता बनाए रखें।

जीआरएमसी में पीजी की 32 सीटें बढ़ीं, 227 सीटों पर मिलेंगे प्रवेश, एनएमसी ने जारी किया आदेश

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय (जीआरएमसी) में परास्नातक (पीजी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने की इच्छा रखने वाले मेडिकल छात्रों के लिए बेहद राहत और खुशी की खबर आई है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने महाविद्यालय के विभिन्न विभागों में पीजी की 32 अतिरिक्त सीटों को बढ़ाने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। इस नई बढ़ोतरी के साथ ही जीआरएमसी में अब पीजी सीटों की कुल संख्या 195 से बढ़कर 227 हो गई है। एनएमसी सचिव डॉ. राघव लंगर की ओर से इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। चिकित्सा शिक्षा में मिलेंगे बेहतर अवसर, 300 सीटों का लक्ष्य पीजी सीटों में हुई इस उल्लेखनीय वृद्धि से राज्य और देश भर के प्रतिभावान विद्यार्थियों को जीआरएमसी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से विशेषज्ञता हासिल करने के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। इस सफलता के बाद अब महाविद्यालय प्रशासन का अगला लक्ष्य पीजी सीटों की कुल संख्या को बढ़ाकर 300 तक पहुंचाना है। इसके साथ ही कॉलेज प्रबंधन की ओर से कुछ नए सुपर स्पेशलिटी और एडवांस्ड कोर्सेज शुरू करने की तैयारियां भी तेजी से की जा रही हैं। अंचल के मरीजों को शहर में ही मिलेगा उन्नत इलाज महाविद्यालय में पीजी सीटों और नए पाठ्यक्रमों के विस्तार का सीधा लाभ ग्वालियर तथा आसपास के पूरे अंचल की आम जनता को मिलेगा। विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या बढ़ने से स्थानीय स्तर पर ही स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुदृढ़ और बेहतर हो सकेंगी। इससे ऐसे कई जटिल रोगों का इलाज अब जीआरएमसी में ही संभव हो सकेगा, जिनके लिए वर्तमान में स्थानीय मरीजों को दिल्ली, मुंबई या अन्य बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है।

झांसी-निजामुद्दीन अनारक्षित ट्रेन के 6 फेरे, ललितपुर से चलेगी एक आरक्षित विशेष ट्रेन

त्योहारी सीजन में दिल्ली के लिए चलेंगी दो विशेष ट्रेनें, ग्वालियर के यात्रियों को राहत

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



आगामी त्योहारों के सीजन में दिल्ली और आसपास के प्रमुख शहरों की ओर जाने वाले यात्रियों की लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। यात्रियों को सुगम और आरामदायक सफर की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से रेलवे प्रशासन ने दो जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इन विशेष ट्रेनों में एक अनारक्षित और दूसरी आरक्षित ट्रेन शामिल होगी। झांसी मंडल के अनुसार, इन दोनों स्पेशल ट्रेनों का ठहराव ग्वालियर सहित मंडल के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रखा गया है। रेलवे के इस फैसले से ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों से दिल्ली की यात्रा करने वाले तथा वहां से वापस लौटने वाले यात्रियों को टिकट बुकिंग और आवागमन के लिए बेहतरीन अतिरिक्त विकल्प मिल सकेगा। झांसी से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलाई जा रही अनारक्षित विशेष ट्रेन कुल छह फेरे पूरे करेगी। रेलवे द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार, गाड़ी संख्या 01901 (झांसी-हजरत निजामुद्दीन स्पेशल) झांसी रेलवे स्टेशन से आगामी सात, आठ, नौ, 11, 12 और 13 नवंबर को रात 7:20 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन अपने निर्धारित मार्ग से होते हुए रात 9:15 बजे ग्वालियर पहुंचेगी और 5 मिनट के ठहराव के बाद रात 9:20 बजे दिल्ली के लिए रवाना होगी। अगले दिन तड़के सुबह 3:00 बजे यह हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचेगी। वहीं वापसी दिशा में, गाड़ी संख्या 01902 दिल्ली से आठ, नौ, 10, 12, 13 और 14 नवंबर को सुबह 4:25 बजे रवाना होगी। दोपहर 1:00 बजे यह ट्रेन ग्वालियर पहुंचेगी और दो मिनट के अल्प विश्राम के बाद 1:02 बजे झांसी के लिए प्रस्थान करेगी। ललितपुर-हजरत निजामुद्दीन आरक्षित ट्रेन का रहेगा 1 फेरा इसके अलावा, यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को समाहित करने के लिए ललितपुर से हजरत निजामुद्दीन के मध्य एक आरक्षित विशेष ट्रेन भी संचालित की जा रही है, जो एक फेरा लगाएगी। यह विशेष गाड़ी 10 नवंबर को ललितपुर से शाम 5:10 बजे प्रस्थान करेगी और रात 9:15 बजे ग्वालियर पहुंचेगी। वापसी मार्ग में यह ट्रेन 11 नवंबर को दिल्ली से सुबह 4:25 बजे रवाना होकर दोपहर 1:00 बजे ग्वालियर पहुंचेगी। यात्रियों की सुविधा और अधिक क्षमता सुनिश्चित करने के लिए इस स्पेशल ट्रेन में कुल 20 कोच लगाए जाएंगे। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन ट्रेनों के संचालन से त्योहारी सीजन में नियमित ट्रेनों पर पड़ रहा दबाव काफी हद तक कम होगा।

संक्षिप्त समाचार

एनसीएलटी ने एसबीआई के 12,668 करोड़ के बकाया मामले में वेणुगोपाल धूत को घोषित किया दिवालिया

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की 12,668



करोड़ रुपए के बकाये के मामले में दायर याचिका स्वीकार कर ली और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के पूर्व प्रवर्तक एवं निदेशक वेणुगोपाल नंदलाल धूत को दिवालिया घोषित कर दिया है। एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने धूत के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया संचालित करने के लिए एक दिवाला न्यासी भी नियुक्त किया है। धूत ने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज की ओर से एसबीआई और उसके पूर्व सहयोगी बैंकों से ली गई ऋण सुविधाओं के लिए व्यक्तिगत गारंटी दी थी। इन सहयोगी बैंकों का बाद में एसबीआई में विलय हो गया था। एनसीएलटी की दो सदस्यीय पीठ ने बृहस्पतिवार को पारित आदेश में कहा, यहां व्यक्तिगत गारंटर वेणुगोपाल नंदलाल धूत को दिवालिया घोषित किया जाता है। एनसीएलटी ने दिवाला न्यासी को निर्देश दिया कि वह धूत के लेनदारों से दावे आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी करे। उसने कहा कि दिवालिया (धूत) की संपत्ति उनके लेनदारों के बीच बांटी जाएगी। धूत को दिवाला कार्यवाही शुरू होने की तारीख से सात दिन के भीतर अपनी वित्तीय स्थिति का विवरण दिवाला न्यासी को सौंपने का निर्देश दिया गया है। आदेश में कहा गया, दिवालिया (धूत) इस आदेश की तारीख यानी दिवाला प्रक्रिया शुरू होने की तारीख से सात दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप में अपनी वित्तीय स्थिति का विवरण दिवाला न्यासी को सौंपेंगे। पीठ ने कहा कि दिवाला न्यासी 90 दिन के भीतर न्यायाधिकरण और लेनदारों की समिति को प्रारंभिक रिपोर्ट भी सौंपेगा। इसके बाद उसे हर तिमाही में प्रगति रिपोर्ट देनी होगी।

डबल मुनाफे के बाद टाइटन शेयर ने पकड़ी रफ्तार, 6150 तक जा सकता है भाव

नई दिल्ली, एजेंसी। शानदार तिमाही नतीजे के बाद टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन कंपनी लिमिटेड के शेयर में जबरदस्त उछाल आया। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को टाइटन कंपनी लिमिटेड के शेयर 4,831.55 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले करीब 4 पर्सेंट उछलकर 5,000 रुपये के स्तर के पार कर गया। इसी के साथ शेयर अपने 52 हफ्ते हाई के करीब आ गया है। बता दें कि शेयर के 52 हफ्ते का हाई 5,187.45 रुपये है। शेयर का यह भाव अगस्त 2026 में था। शेयर के फ्यूचर को लेकर एक्सपर्ट बुलिश भी हैं। आइए शेयर के टारगेट प्राइस और तिमाही नतीजे के बारे में जान लेते हैं। ब्रोकरेज नोमुरा ने टाइटन के शेयर पर अपनी 'खरीदें' रेटिंग को बरकरार रखा है और इसका टारगेट प्राइस 5425 प्रति शेयर से बढ़ाकर 6150 प्रति शेयर कर दिया है। यह इस शेयर के लिए अब तक का सबसे ऊंचा टारगेट प्राइस है। इसके अलावा, जेफरीज ने टाइटन के शेयर पर अपनी रेटिंग को अपग्रेड करके 'बाय' की रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस बढ़ाकर 6,000 कर दिया है। वहीं, क्रेडिट सुइस और सिटी ने भी अपनी 'बाय' रेटिंग बरकरार रखी है। जेपी मॉर्गन की रेटिंग 'न्यूट्रल' है। चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में टाइटन कंपनी लिमिटेड का मुनाफा दोगुने से अधिक होकर 2,393 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने बीते वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में 1,120 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। टाइटन ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में परिचालन से कंपनी का राजस्व 23.54 प्रतिशत बढ़कर 20,337 करोड़ रुपये हो गया। यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 16,461 करोड़ रुपये था। हालांकि, कंपनी की राजस्व वृद्धि की रफ्तार पिछली तिमाहियों के मुकाबले धीमी रही है।

अडानी की झोली में आएगी एक और विदेशी कंपनी

यूरोप की इवोस के साथ 27 हजार करोड में होगी डील

नई दिल्ली, एजेंसी। अडानी ग्रुप अपने बिजनेस का विस्तार करने के लिए लगातार दूसरी कंपनियों का अधिग्रहण कर रहा है। अब अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूरोप की लिक्विड स्टोरेज कंपनी इवोस बीवी का अधिग्रहण करेगी। कंपनी ने गुरुवार को बताया कि यह सौदा 2.88 अरब डॉलर (करीब 2.56 अरब यूरो यानी करीब 27 हजार करोड़ रुपये) के एंटरप्राइज वैल्यू पर होगा। यह पूरी तरह नकद में होने वाला सौदा है। इवोस की वैल्यू 1.18 अरब यूरो आंकी गई है। यह सौदा कंपनी के साल 2025 के श्वङ्क/ईबीआईटीडीए के 11.7 गुना पर हुआ है। अधिग्रहण के लिए अडानी पोर्ट्स कर्ज के जरिए रकम जुटाएगी। हालांकि इस सौदे को नियामकीय मंजूरी और दूसरी जरूरी मंजूरियां मिलना बाकी है। इसके अलावा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की जाएगी।

कैलेंडर ईयर 2025 में 392 मिलियन यूरो का रेवेन्यू दर्ज किया था। इस दौरान कंपनी का ईबीआईटीडीए 219 मिलियन यूरो रहा। कंपनी का ईबीआईटीडीए मार्जिन 56% था। अडानी पोर्ट्स के वित्तीय आंकड़ों के आधार पर दोनों कंपनियों का संयुक्त नेट डेट-टू-ईबीआईटीडीए अनुपात 2.76 गुना रहने का अनुमान है। इसके वित्त वर्ष 2027 तक घटकर करीब 2.5 गुना होने की उम्मीद है।

इवोस का अधिग्रहण कंपनी के 1 अरब टन कार्गो संभालने के लक्ष्य की दिशा में एक अहम कदम है। इससे कंपनी को दुनिया के प्रमुख लिक्विड स्टोरेज और ऊर्जा केंद्रों में अपनी मौजूदगी बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस सौदे से कंपनी को यूरोप के ऊर्जा बाजार में अपनी जगह मजबूत करने और वहां स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ते



बदलाव में भागीदारी का मौका मिलेगा।

इवोस यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी स्वतंत्र लिक्विड स्टोरेज कंपनी है। यह कंपनी पेट्रोल, डीजल, समुद्री जहाजों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन और विमान ईंधन के भंडारण का काम करती है। इसके अलावा कंपनी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल , बायोफ्यूल, मेथनॉल और बायोएथेनॉल जैसे नए ईंधनों से जुड़े कारोबार में भी मौजूद है। कंपनी के पास नीदरलैंड, जर्मनी, स्पेन, बेल्जियम और माल्टा में बंदरगाहों पर बने टर्मिनल हैं। इनकी कुल स्टोरेज क्षमता 63 लाख क्यूबिक मीटर है। कंपनी ने साल 2025 में 3.7 करोड़ मीट्रिक टन सामान का संचालन किया था। अडानी ग्रुप ने साल 2014 से लेकर अब तक कई बड़ी कंपनियों और संपत्तियों का किया अधिग्रहण है।

पोर्ट और लॉजिस्टिक्स में बढ़ाया नेटवर्क

अडानी ग्रुप का पारंपरिक कारोबार पोर्ट और लॉजिस्टिक्स से जुड़ा रहा है। इस क्षेत्र में भी समूह ने कई बड़े अधिग्रहण किए हैं। आंध्र प्रदेश के गंगावरम पोर्ट और कृष्णापट्टनम पोर्ट को समूह ने अपने पोर्ट नेटवर्क में शामिल किया। इसके अलावा, समुद्री सेवाएं देने वाली कंपनी ओशन स्पार्कल का भी अधिग्रहण किया गया। अडानी ग्रुप ने एयरपोर्ट सेक्टर में भी तेजी से विस्तार किया। लक्ष्य ग्रुप के साथ हुए सौदे के जरिए मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नियंत्रण हासिल किया गया। इसके अलावा नवी मुंबई एयरपोर्ट परियोजना में भी समूह की बड़ी हिस्सेदारी है। समूह को अहमदाबाद, गुवाहाटी, जयपुर, लखनऊ, मंगलुरु और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के संचालन की जिम्मेदारी भी मिली। इन एयरपोर्ट को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लीज पर लिया गया था। अडानी ग्रुप ने बिजली और ऊर्जा कारोबार में भी अधिग्रहण के जरिए अपनी मौजूदगी बढ़ाई। दिसंबर 2017 में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के पावर ट्रांसमिशन कारोबार से जुड़ी संपत्तियों के अधिग्रहण का सौदा किया गया था। इस सौदे की कीमत करीब 18,800 करोड़ रुपये बताई गई थी। मीडिया सेक्टर में अडानी ग्रुप ने साल 2022 में एएमजी मीडिया नेटवर्क्स के जरिए एनडीटीवी का अधिग्रहण किया। इससे अडानी ग्रुप ने मीडिया कारोबार में भी कदम रखा।

वाहन खुदरा बिक्री अक्टूबर में 23.8 प्रतिशत घटकर 31.72 लाख इकाई रही: फाडा

नई दिल्ली, एजेंसी। देश में वाहनों की खुदरा बिक्री अक्टूबर में सालाना आधार पर 23.8 प्रतिशत घटकर 31.72 लाख से अधिक इकाई रह गई। उद्योग निकाय फाडा ने यह जानकारी दी। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (फाडा) के आंकड़ों के अनुसार, बिक्री में यह गिरावट इसलिए भी रही क्योंकि इस साल धनतेरस और दिवाली नवंबर में पड़ रहे हैं, जबकि पिछले साल नवरात्र तथा दिवाली दोनों अक्टूबर में थे। इसके अलावा, माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती के बाद पिछले साल मांग में आई तेज उछाल का भी असर था। दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री अक्टूबर में 28.35 प्रतिशत घटकर 23.21 लाख इकाई रही, जबकि यात्री वाहनों की बिक्री 4.23 प्रतिशत फिसलकर 5.08 लाख इकाई पर आ गई। फाडा के अध्यक्ष साई गिरिधर ने कहा, अक्टूबर भारत में साल का सबसे बड़ा खुदरा बिक्री वाला महीना होता है और इस साल इसके आंकड़ों को त्योहारों के कैलेंडर को ध्यान में रखकर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सालाना आधार पर आई गिरावट लगभग पूरी तरह आंकड़ों में दिखने वाला असर है। गिरिधर ने कहा, पिछले साल अक्टूबर असाधारण महीना था, जब नवरात्र और दीपावली दोनों एक साथ पड़े थे। इसके अलावा, 22 सितंबर, 2025 को जीएसटी दरों में कटौती के बाद दबी हुई मांग भी बाजार में आई थी।

मृत कर्मचारी के जीपीएफ पैसा पर पहला हक परिवार का

नई दिल्ली , एजेंसी। जीपीएफ यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड सरकार की एक पेंशन योजना है। इसे आसान भाषा में समझें तो यह पुरानी पेंशन योजना का पालन करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एक रिटायरमेंट योजना है। इस योजना की खास बात यह है कि इसकी सुविधा एनपीएस और यूपीएस से जुड़े कर्मचारियों को नहीं



मिलती है। अब केंद्र सरकार ने जीपीएफ को लेकर एक नियम की जानकारी दी है। आमतौर पर देखा जाता था कि सरकारी कर्मचारियों की असामयिक मृत्यु के बाद उनके प्रोविडेंट फंड के पैसों को लेकर विवाद हो जाता था। सवाल यह होता था कि यह पैसा बाहरी नॉमिनी को दिया जाएगा या उनकी फैमिली को। अब इस झंझट को सरकार ने खत्म कर दिया है। आइए जानते हैं पूरी खबर।

मिली जानकारी के अनुसार, बीते 29 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने जीपीफ फंड को लेकर एक बड़ा फैसला किया। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने अपने ऑफिस मेमोरैंडम में नियमों को स्पष्ट करते हुए बताया कि मृत कर्मचारियों के जीपीएफ का पैसा किसे मिलेगा। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि किसी सरकारी कर्मचारी के निधन पर जब मामला उसके जीपीएफ फंड के क्लेम और भुगतान का आएगा तो इसपर पहला हक उसके परिवार का होगा। सरकार ने यह भी बताया कि बाहरी नॉमिनी होने के बावजूद भी मृत कर्मचारी के जीपीएफ पैसा पर पहला हक उसकी फैमिली (परिवार) का ही होगा। हर महीने बचत करके कैसे बनाएं मोटा पैसा बड़े काम के हैं निवेश के ये ऑप्शन; आपने देखा क्यायह भी पढ़ें:हर महीने बचत करके कैसे बनाएं मोटा पैसा बड़े काम के हैं निवेश के ये ऑप्शन; आपने देखा क्या सरकार ने जीपीएफ पैसा को लेकर दो स्थितियों को स्पष्ट किया है। पहली कि जब कर्मचारी की मृत्यु जीपीएफ का पैसा भुगतान होने से पहले हो जाती है। दूसरी स्थिति कि जब कर्मचारी की मृत्यु हो गई होती है, पैसा भुगतान हो चुका है या भुगतान होना बाकी है। सरकार ने अपने नियम में यह बात साफ किया है कि यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और जब नॉमिनी परिवार से ही होता है तो उसे जीपीएफ का पूरा पैसा मिलेगा। अगर नॉमिनी में एक से अधिक लोग हैं तो पैसा नॉमिनेशन में दिए गए हिस्से (अनुपात) के हिसाब से बांट दिया जाएगा। आखिर रिटायरमेंट प्लानिंग की इतनी जरूरत क्यों इन 5 बातों से समझें इसकी अहमियतयह भी पढ़ें:आखिर रिटायरमेंट प्लानिंग की इतनी जरूरत क्यों इन 5 बातों से समझें इसकी अहमियत जब नॉमिनी परिवार से ना हो, या कोई वैध नॉमिनी ना हो या फिर जहां नॉमिनेशन में केवल आधी-अधूरी राशि का ही जिक्र किया गया हो तो ऐसे में जीपीएफ का पूरा पैसा मृत कर्मचारी की फैमिली को दे दी जाएगी। उसके परिवार के योग्य सदस्यों को यह पैसा बराबर-बराबर करके बांट दिया जाएगा। अगर नॉमिनी परिवार से नहीं बल्कि बाहर से है तब भी जीपीएफ का पैसा फैमिली को ही दी जाएगी।

2.5 ट्रिलियन स्वाहा! अमेरिकी शेयर बाजार में हाहाकार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को ठहराया जिम्मेदार

नई दिल्ली, एजेंसी। अमेरिका के शेयर बाजार में गुरुवार को भारी गिरावट देखने को मिली। देश में हाल में हुए मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेट्स की जीत के कारण निवेशकों को आशंका है कि एआई पर हो रहे भारी निवेश पर ब्रेक लग सकता है। इससे टेक शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। नैसडैक में कारोबार के दौरान 6.4 फीसदी फिसल गया जो 2020 में कोरोना काल के बाद इसमें एक दिन में आई सबसे बड़ी गिरावट है। इस गिरावट से निवेशकों के 2.5 ट्रिलियन डॉलर स्वाहा हो गए। नैसडैक अंत में 5.54 फीसदी गिरावट के साथ बंद हुआ। यह 6 अक्टूबर के हाई से 10 फीसदी नीचे आ चुका है। एसएंडपी 500 और डाउ जोंस ने भी अप्रैल 2025 के बाद अपनी सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की। अमेरिकी शेयर बाजार में आई गिरावट का असर ग्लोबल मार्केट पर भी दिखाई दे रहा है। साउथ कोरिया का मार्केट खुलते ही करीब 9 फीसदी गिर गया और कोस्पी इंडेक्स पर करीब 20 मिनट के लिए ट्रेडिंग रोकनी पड़ी।

इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर बाजार में आई भारी गिरावट के लिए डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहराया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, 'रिजल्ट के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है। यह इतिहास की बड़ी गिरावटों में से एक है। यह देखना दुःखद है। यहां तक पहुंचने के लिए हमने काफी मेहनत की थी और फिर यह



सबकुछ। आपका 401 (के) ड्रॉप हो गया। याद रखिए इसके लिए रिपब्लिकन नहीं, डेमोक्रेट्स जिम्मेदार हैं।'

अमेरिका में 401(के) एम्प्लॉयर द्वारा प्रायोजित एक रिटायरमेंट सेविंग्स स्कीम है। इसका नाम 'इंटरनल रेवेन्यू कोड' के सेक्शन 401(के) के नाम पर रखा गया है। यह वर्कर्स को अपनी सैलरी का एक हिस्सा टैक्स कटने से पहले या बाद में बचाने और निवेश करने की सुविधा देती है। इससे पहले बुधवार को यूएस मार्केट में तेजी आई थी। लेकिन गुरुवार की गिरावट ने उस पर पानी फेर दिया। रिजल्ट के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है। यह इतिहास की बड़ी गिरावटों में से एक है। यह देखना दुःखद है। यहां तक पहुंचने के लिए हमने काफी मेहनत की थी और फिर यह सबकुछ। आपका 401 (के) ड्रॉप हो गया। याद रखिए इसके लिए रिपब्लिकन नहीं, डेमोक्रेट्स जिम्मेदार हैं। मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेट्स की बंपर जीत के बाद भारी बिकवाली देखने को मिली। डेमोक्रेट्स ने कई ऐसे राज्यों में भी जीत हासिल की है जहां डेटा सेंटर्स के खिलाफ विरोध बढ़ रहा है। निवेशकों को आशंका है कि आने वाले दिनों में एआई बूम की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। इससे एआई से जुड़े शेयरों में भारी गिरावट आई। एनवीडिया को शेयर 9.3 फीसदी लुढ़क गया और इसके साथ ही उसने इस साल की पूरी कमाई एक झटके में गंवा दी। एलन मस्क की टेस्ला और स्पेसएक्स में भी क्रमशः 11 फीसदी और 9 फीसदी गिरावट आई।

ब्लिंकिट एंबुलेंस फ्री यूज करने में ग्लानि होती है जल्दी ही कर सकेंगे 'स्वैच्छिक भुगतान'

नई दिल्ली , एजेंसी। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकइट की एंबुलेंस सेवा इन दिनों चर्चा में है। चर्चा की वजह ज़ोमैटो और ब्लिंकइट के फाउंडर दीपिंदर गोयल का एक ट्वीट है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्वीटर) पर गुरुवार को किए गए इस पोस्ट में उन्होंने कहा है कि अब ब्लिंकिट की सभी एंबुलेंस सेवाएं फ्री नहीं होंगी। क्योंकि लोग इस सेवा का उपयोग कम दुरुपयोग ज्यादा करते हैं। इसके बाद एक व्यक्ति ने कहा कि वह उनकी इमरजेंसी सर्विस का यूज करके प्रभावित हैं। वह इसके लिए भी पेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन वह कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं।

गुरुवार, 5 नवंबर को दिन में सवा बारह बजे गोयल ने एक ट्वीट का जवाब दिया था। इस पोस्ट में कहा गया था कि ब्लिंकिट एंबुलेंस ने उनकी ग्रैंडमा का जीवन बचा लिया। वह लिखते



हैं कि महज 8 मिनट में जिस तरह से उनका एंबुलेंस आया और त्वरित प्रोफेशनल सर्विस मिली, इस तरह की सेवा को किसी हॉस्पिटल के एंबुलेंस में भी नहीं मिलती। स्पर्श सहगल के इसी पोस्ट पर दीपिंदर गोयल ने लंबा-चौड़ा जवाब लिखा। उन्होंने लिखा 'मैंने ब्लिंकिट एंबुलेंस सेवा की शुरुआत सेवा भाव से की थी। बीते दो साल के दौरान इस सेवा का लाभ करीब 42,000 केसेज में उठाया गया। उनमें से महज 20,000 केसेज ही इमरजेंसी थे। बांकी रूटीन चेक-अप, हॉस्पिटल विजिट, अस्पताल से घर लौटने वाले मरीज थे। ऐसे मरीज आराम से उबर या किसी अन्य प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का लाभ ले सकते थे। उनके लिए फुल्ली इक्विप्ड एंबुलेंस की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए अब सिर्फ इमरजेंसी ट्रांसफर ही फ्री होगी। नॉन-इमरजेंसी ट्रांसफर के लिए ढाई हजार रुपये चार्ज किए जाएंगे। वह आगे लिखते हैं कि पेड एंबुलेंस सर्विस से जो पैसे मिलेंगे, वह कंपनी की धर्मार्थ संस्था इंटरनल फाउंडेशन को दे दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यही संस्था ब्लिंकिट एंबुलेंस का संचालन करती है। उनका कहना है कि नॉन-इमरजेंसी ट्रांसफर से जो भी पैसे आएंगे, उससे इस तरह की सेवा का और विस्तार करने में मदद मिलेगी। अभी तो यह सेवा सिर्फ महानगरों में उपलब्ध है।

बर्तन धोने से शुरू किया सफर, आज 15 रेस्टोरेंट के मालिक, 111 करोड़ का कारोबार, कभी 35 रुपये लेकर आए थे मुंबई

नई दिल्ली, एजेंसी। मुंबई में आज शिव सागर का नाम मशहूर रेस्टोरेंट ब्रांड के तौर पर जाना जाता है। यहां लोग पाव भाजी से लेकर पिज्जा और कई तरह के दूसरे व्यंजनों का स्वाद लेने आते हैं। लेकिन इस ब्रांड की शुरुआत किसी बड़े निवेश या आलीशान रेस्टोरेंट से नहीं हुई थी। इसके पीछे नारायण टी पुजारी का संघर्ष है, जो महज 13 साल की उम्र में जेब में 35 रुपये लेकर कर्नाटक के एक छोटे से गांव से मुंबई आए थे।

उन्होंने छोटे होटलों में बर्तन धोने और फर्श साफ करने से शुरुआत की। आगे चलकर उन्होंने एक छोटी आइसक्रीम की दुकान खोली, जो धीरे-धीरे शिव सागर जैसे बड़े रेस्टोरेंट ब्रांड में बदल गई। नारायण टी. पुजारी कर्नाटक के उडुपी जिले के गुज्जाडी गांव के रहने वाले हैं। उनका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। परिवार की मदद करने और रोजी-रोटी कमाने के लिए उन्होंने कम उम्र में ही मुंबई आने का फैसला किया। मुंबई पहुंचने के बाद उनका जीवन आसान नहीं था। उन्होंने दक्षिण मुंबई के छोटे होटलों और कैंटीन में काम किया।



कभी बर्तन धोए, कभी टेबल साफ कीं तो कभी फर्श की सफाई की। दिनभर मेहनत करने के बाद भी उन्होंने पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया। वह दिन में काम करते और रात में स्कूल जाते थे। काम के दौरान नारायण की मुलाकात मर्चेंट नेवी के युवा कैडेट्स से होती थी। उनकी बातें और काम के प्रति अनुशासन ने नारायण को काफी प्रभावित किया। उनसे बातचीत करके उन्हें समझ आया कि जिंदगी में सिर्फ रोज की कमाई तक सीमित रहने के बजाय कुछ बड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए। धीरे-धीरे उनके भीतर अपना कारोबार शुरू करने का सपना मजबूत होने लगा। उन्होंने काम के साथ-साथ लोगों को समझना और उनसे सीखना जारी रखा। साल 1990 में नारायण ने मुंबई के फोर्ट इलाके में आइसक्रीम की एक छोटी दुकान शुरू की। कारोबार की शुरुआत में वह खुद ही खाना बनाने, सफाई करने और दुकान के रोजमर्रा के काम संभालते थे। कारोबार को लेकर कोई पक्की गारंटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेहनत जारी रखी। इसी दौरान एक ग्राहक ने उन्हें दुकान पर पाव भाजी बेचने का सुझाव दिया। नारायण ने इस सलाह को अपनाया और मेन्यू में पाव भाजी शामिल कर दी। यह फैसला उनके कारोबार के लिए बड़ा मोड़ साबित हुआ। 14 लाख सैन्यकर्मियों के वाहनों को टोल में छूट, गडकरी के सड़क और राजनाथ के रक्षा मंत्रालय में बातचीत शुरूयह भी पढ़ें:14 लाख सैन्यकर्मियों के वाहनों को टोल में छूट, गडकरी के सड़क और राजनाथ के रक्षा मंत्रालय में बातचीत शुरू पाव भाजी को ग्राहकों ने खूब पसंद किया। धीरे-धीरे दुकान पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी और रोजाना सैकड़ों प्लेट बिकने लगीं। नारायण को समझ आ गया कि ग्राहकों की पसंद को समझना और समय के साथ मेन्यू में बदलाव करना फूड बिजनेस के लिए जरूरी है। उन्होंने अपने मेन्यू में भी नए व्यंजन शामिल किए। 2000 के शुरुआती वर्षों में उन्होंने पिज्जा, मैक्सिकन फूड और भारतीय स्वाद वाले नए व्यंजनों को जगह दी। इस तरह उन्होंने पारंपरिक भारतीय खाने के साथ नए विकल्प भी ग्राहकों को देने शुरू किए।

एलन मस्क ने एक दिन में गंवा दी 9% से ज्यादा दौलत, अमीरों की लिस्ट में ऊपर चढ़े मुकेश अंबानी

नई दिल्ली, एजेंसी। अमेरिकी शेयर बाजार में गुरुवार को भारी गिरावट आई। निवेशकों को आशंका है कि मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेट्स की भारी जीत के कारण एआई पर हो रहे खर्च पर लगाम लग सकती है। इससे बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली। इस गिरावट के कारण दुनिया के टॉप 10 अमीरों की नेटवर्थ भी फिसल गई। सबसे ज्यादा झटका एलन मस्क को लगा। दुनिया के सबसे बड़े रईस की नेटवर्थ एक झटके में 9 फीसदी से ज्यादा गिर गई। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के मुताबिक मस्क की नेटवर्थ में 79.7 अरब डॉलर की गिरावट आई है। इसके साथ ही उनकी नेटवर्थ 785 अरब डॉलर रह गई है। मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का शेयर गुरुवार को 9.05 फीसदी गिरावट के साथ बंद हुआ जबकि टेस्ला में 10.77 फीसदी गिरावट आई। वैसे इस साल मस्क की नेटवर्थ में 312 अरब डॉलर की तेजी आई है।

चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया के शेयरों में भी भारी गिरावट आई। इससे कंपनी के फाउंडर और सीईओ जेंसन हुआंग की नेटवर्थ 15.1 अरब की गिरावट के साथ 151 अरब डॉलर रह गई और वह दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 13वें नंबर पर फिसल गए। डेल कॉरपोरेशन के माइकल डेल ने 19.4 अरब डॉलर गंवा दिए और उनकी नेटवर्थ 190 अरब डॉलर रह गई है। ऐमजॉन के फाउंडर



जेफ बेजोस ने 4.99 अरब डॉलर गंवाए जबकि लैरी पेज को 4.24 अरब डॉलर का झटका लगा। इसी तरह सर्गेई ब्रिन की नेटवर्थ 3.88 अरब डॉलर कम हो गई जबकि फेसबुक के मार्क जकरबर्ग की नेटवर्थ में 8.41 अरब डॉलर की गिरावट आई। टॉप 10 रईसों में शामिल वॉरेन बफे ने 2.26 अरब डॉलर और लैरी एलिसन ने 10.1 अरब डॉलर गंवाए। इस बीच भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को भारी तेजी रही। इससे भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस गौतम अडानी की नेटवर्थ में 1.12 अरब डॉलर की तेजी आई। वह 117 अरब की नेटवर्थ के साथ दुनिया में 18वें नंबर पर हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 51 करोड़ की तेजी के साथ 87.3 अरब पहुंच गई और वह अमीरों की लिस्ट में एक स्थान चढ़कर 22वें नंबर पर आ गए।

एशियाई पेरा गेम्स में भारत ने जीते सात कांस्य पदक, प्रशिक्षक जयेश आचार्य और ललन दोषी को भी मिला सम्मान

कांस्य पदक जीतने पर प्रधानमंत्री ने भारतीय पेरा टेबल टेनिस दल को किया सम्मानित

एक सत बुलेटिन, इंदौर

जापान के आइची-नागोया में आयोजित पांचवें एशियाई पेरा गेम्स में भारतीय पेरा टेबल टेनिस खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और सात कांस्य पदक जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में इंदौर के प्रशिक्षक जयेश आचार्य और टीम के प्रशिक्षक ललन दोषी भी शामिल रहे। इस उपलब्धि से इंदौर के खेल जगत में खुशी का माहौल है। मध्य प्रदेश पेरा टेबल टेनिस प्रमोशन एसोसिएशन के अध्यक्ष ओम सोनी और महासचिव प्रमोद गंगराड़े ने बताया कि पांचवें एशियाई पेरा गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 114 पदक हासिल किए और पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया। इनमें पेरा टेबल टेनिस के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और मेहनत का परिचय देते हुए सात कांस्य पदक देश के नाम किए।



इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों से मुलाकात कर उनके प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने खिलाड़ियों के संघर्ष, मेहनत और खेल के प्रति समर्पण की प्रशंसा करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी मौजूद थीं। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से भाविना पटेल, जेडी मदन और सोनल पटेल सहित भारतीय पेरा टेबल टेनिस दल के खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना की। उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। खिलाड़ियों की इस सफलता में प्रशिक्षकों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना गया, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने में मार्गदर्शन और प्रशिक्षण दिया। इंदौर के प्रशिक्षक जयेश आचार्य ने सम्मानित किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि देश में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई योजनाओं और उनके प्रभावी क्रियान्वयन से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के बेहतर अवसर मिल रहे हैं। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, सुविधाएं और प्रोत्साहन मिलने से वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर पा रहे हैं। उन्होंने इस उपलब्धि को पूरी टीम की मेहनत और सामूहिक प्रयास का परिणाम बताया। जयेश आचार्य को मिले इस सम्मान से मध्य प्रदेश और विशेष रूप से इंदौर के टेबल टेनिस जगत में प्रसन्नता व्यक्त की जा रही है। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस संगठन के चेयरमैन ओम सोनी, नरेंद्र कौशिक, प्रमोद सोनी, रिंकू आचार्य, प्रमोद गंगराड़े, नीलेश वेद, गौरव पटेल और अमित कोटिया ने जयेश आचार्य की उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खिलाड़ियों की सफलता और प्रशिक्षकों को मिलने वाला सम्मान प्रदेश के अन्य खिलाड़ियों एवं खेल प्रशिक्षकों के लिए भी प्रेरणादायक है। इससे पेरा खेलों को नई पहचान मिलने के साथ दिव्यांग खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

बाल संरक्षण आश्रम में बच्चों के बीच पहुंचे कलेक्टर, साथ मनाई दीपावली



एक सत बुलेटिन, इंदौर

दीपावली का पर्व खुशियां बांटने और अपनों के साथ समय बिताने का त्योहार है। इसी भावना के साथ इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने दीपावली के अवसर पर शासकीय बाल संरक्षण आश्रम पहुंचकर वहां रहने वाले बच्चों के साथ पर्व की खुशियां साझा कीं। कलेक्टर को अपने बीच पाकर बच्चे भी काफी उत्साहित नजर आए। इस दौरान उन्होंने बच्चों को उपहार, नए वस्त्र और मिठाइयां वितरित कीं। साथ ही बच्चों के साथ आतिशबाजी कर दीपावली का उत्सव मनाया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में कलेक्टर शिवम वर्मा ने बच्चों से आत्मीयता के साथ बातचीत की और उनकी कुशलक्षेम जानी। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई, दिनचर्या और आश्रम में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। उपहार और मिठाइयां पाकर बच्चों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। कलेक्टर ने बच्चों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए उनके साथ कुछ समय बिताया और उन्हें प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि बच्चों के बीच दीपावली मनाना उनके लिए सुखद अनुभूति है। बच्चे देश का उज्ज्वल भविष्य हैं और उनके जीवन में खुशियां लाना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आश्रम में रहने वाले बच्चों को भी त्योहारों के अवसर पर परिवार जैसा अपनापन, स्नेह और खुशियां मिलें, यही इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। त्योहार केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं होते, बल्कि एक-दूसरे के साथ खुशियां बांटने और रिश्तों में आत्मीयता बढ़ाने का माध्यम भी हैं।

रहवासी इलाके में अवैध गैस रिफिलिंग का कारोबार, दो आरोपी गिरफ्तार



एक सत बुलेटिन, इंदौर

शहर के रहवासी इलाकों में अवैध रूप से गैस सिलेंडरों का भंडारण करने और उनमें गैस की रिफिलिंग कर ऊंचे दामों पर बेचने के मामले में मल्हारगंज थाना पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडरों का अवैध कारोबार कर रहे थे। वे जरूरतमंद लोगों और आयोजनों के लिए गैस टंकियों की व्यवस्था करने वालों को साढ़े तीन हजार से लेकर चार हजार रुपए तक में सिलेंडर बेचते थे। पुलिस ने मौके से गैस टंकियां भी बरामद की हैं।

पुलिस के मुताबिक, मामला मल्हारगंज थाना क्षेत्र के रामगंज जिंसी स्थित गोल मंदिर के पास का है। यहां घनी आबादी वाले रहवासी इलाके में अवैध रूप से गैस सिलेंडरों का भंडारण और रिफिलिंग किए जाने की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी नीरज बिरथरे ने मामले की जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद थानेदार रविराज सिंह बैंस, प्रधान आरक्षक कुसुम टंडन और आरक्षक धर्मेंद्र जाट, महेंद्र एवं दीपक गुप्ता की टीम ने योजना बनाकर कार्रवाई की। पुलिसकर्मी ग्राहक बनकर संबंधित स्थान पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी जुटाई। आरोपियों की गतिविधियों की पुष्टि होने के बाद पुलिस टीम ने दबिश देकर दोनों को पकड़ लिया।

पुलिस ने मौके से रामगंज जिंसी निवासी आदर्श उर्फ भय्यू और उसके साथी तनिष्क पिता हरिनारायण भावसार निवासी देवास को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तनिष्क देवास में कैटरिंग का काम करता है। वह शादी-विवाह और अन्य आयोजनों में इस्तेमाल होने वाली गैस टंकियों के ऑर्डर लेकर आता था। इसी के जरिए वह गैस सिलेंडरों की व्यवस्था और बिक्री के इस अवैध कारोबार से जुड़ा हुआ था। जांच में सामने आया कि आरोपी घरेलू और कमर्शियल गैस टंकियों का अवैध भंडारण करने के साथ ही गैस की रिफिलिंग भी करते थे। इसके बाद इन सिलेंडरों को साढ़े तीन हजार से चार हजार रुपए तक में बेचा जाता था। जरूरतमंद लोगों और आयोजनों में गैस की आवश्यकता रखने वालों को निशाना बनाकर उनसे मनमानी कीमत वसूली जाती थी। घनी आबादी वाले इलाके में इस तरह गैस सिलेंडरों का भंडारण और रिफिलिंग करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता था। गैस का रिसाव, आग लगने या विस्फोट जैसी घटना होने पर आसपास के मकानों और लोगों की जान को गंभीर खतरा पैदा हो सकता था।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत चैत्यभूमि मुंबई की यात्रा 15 नवंबर से

मुरैना। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत डॉ. अम्बेडकर चैत्यभूमि स्मारक, मुंबई की तीर्थ यात्रा का संशोधित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तीर्थ यात्रा 15 नवंबर 2026 को प्रारंभ होगी तथा 18 नवंबर 2026 को यात्रियों की वापसी होगी। संचालनालय धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, मध्यप्रदेश द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत यात्रा में शामिल होने के इच्छुक पात्र हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 9 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। अपर कलेक्टर द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परीक्षण कर पात्र हितग्राहियों का चयन किया जाए। पात्र तीर्थ यात्रियों की सूची निर्धारित प्रारूप में तैयार कर निर्धारित समय-सीमा में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रशासन द्वारा पात्र हितग्राहियों से निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है।



विशेष प्रतिभावान खिलाड़ियों को 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग में भी मिलेगा अवसर

हॉकी फीडर सेंटर मुरैना में प्रवेश के लिए 16 नवंबर को होगा चयन ट्रायल, 8-14 वर्ष के बालक-बालिकाएं ले सकेंगे भाग

एक सत बुलेटिन, मुरैना

मध्यप्रदेश शासन के खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित हॉकी फीडर सेंटर मुरैना में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए प्रतिभाशाली बालक एवं बालिका खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। इसके अंतर्गत 16 नवंबर 2026 को जिला स्तरीय चयन ट्रायल आयोजित किया जाएगा। खेल और युवा कल्याण विभाग के संयुक्त संचालक श्री प्रशांत कुमार कुशवाह ने बताया कि हॉकी फीडर सेंटर में नवीन प्रतिभावान खिलाड़ियों के चयन के लिए 8 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाएं भाग ले सकेंगे। वहीं, विशेष प्रतिभावान खिलाड़ियों के चयन के लिए 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों को भी अवसर प्रदान किया जाएगा। खिलाड़ियों की आयु की गणना 31 अक्टूबर 2026 की स्थिति में की जाएगी। उन्होंने इच्छुक खिलाड़ियों, अभिभावकों, प्रशिक्षकों एवं खेल प्रेमियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक प्रतिभावान बच्चों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि जिले की उभरती हॉकी प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण एवं खेल कौशल विकसित करने का अवसर मिल सके। चयन ट्रायल में शामिल होने के लिए खिलाड़ियों को जन्म प्रमाण पत्र, बोर्ड की अंकसूची, आधार कार्ड, स्थानीय मूल निवासी संबंधी दस्तावेजों की छायाप्रति तथा दो पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ उपस्थित होना होगा। चयन ट्रायल 16 नवंबर 2026 को प्रातः 9 बजे डॉ. भीमराव अंबेडकर स्टेडियम, मुरैना में आयोजित किया जाएगा। इच्छुक खिलाड़ी निर्धारित समय पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। चयन संबंधी अधिक जानकारी के लिए हॉकी प्रशिक्षक श्रीमती दिव्यांशी बघेल (मोबाइल नंबर 7999631189) एवं श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला (मोबाइल नंबर 9301065512) से संपर्क किया जा सकता है।



04 क्विंटल मावा की रिपोर्ट फैल आने पर कम्पोस्ट पिट में किया विनष्टीकरण, मावे को नियमानुसार नष्ट कराया

एक सत बुलेटिन, भिण्ड

जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग और नगर परिषद मालनपुर ने त्वरित और संयुक्त कार्रवाई की। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर 2026 को जब्त किए गए 4 क्विंटल मावा की रिपोर्ट फैल आने पर उसे नगर परिषद के कम्पोस्ट पिट में विनष्टीकरण किया गया, ताकि यह माल पुनः विक्रय या उपभोग के लिए बाजार में न पहुंच सके। यह कार्रवाई नगर परिषद अध्यक्ष, नगर परिषद सीएमओ, बीएमओ गोहद श्री दिलीप सिंह भदौरिया, सैनेटरी इंस्पेक्टर श्री बृजेश किरार, प्लांट इंचार्ज श्री श्यामसुंदर गौड़ की उपस्थिति में की गई। इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुश्री रेखा सोनी एवं श्रीमती रीना बंसल भी मौजूद रहीं। टीम ने मावे को नियमानुसार कम्पोस्ट पिट में नष्ट कराया। अधिकारियों ने कहा कि खराब या अनुपयुक्त खाद्य सामग्री का तुरंत निपटान जरूरी है, ताकि नगरवासियों के स्वास्थ्य पर कोई खतरा न बने। खाद्य सुरक्षा विभाग ने व्यापारियों से अपील की है कि वे खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, सफाई और सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन करें। खाद्य सुरक्षा विभाग निरंतर निरीक्षण कर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करेगा।



हर घर दीया अभियान: मजदूरों को दीए की किट वितरित, सीईओ जिला पंचायत ने स्वयं पहुंचकर वितरण किया

भिण्ड। जिला कलेक्टर श्री पवन जैन के निर्देशन में 'हर घर दीया, घर-घर दीया' अभियान के तहत मुडियाखेड़ा में मजदूरों को दीया, बाती और तेल के पैकेट वितरित किए गए। यह अनूठी पहल जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई। इसमें आनंद विभाग की भी सक्रिय भागीदारी रही। सीईओ जिला पंचायत श्री वीरसिंह चौहान ने स्वयं पहुंचकर मजदूरों को दीया किट वितरित की। इस अभियान का उद्देश्य दिवाली के पर्व पर हर घर में खुशियों का संचार करना और किसी भी परिवार को अंधेरे में नहीं छोड़ना है। दीयों की रोशनी से घर-घर में उत्सव और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश दिया गया। प्रशासन का मानना है कि त्योहारों का आनंद हर वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए ऐसी सामाजिक पहल प्रेरणादायक हैं। मजदूरों ने इस पहल की सराहना की और दिवाली की शुभकामनाएं दीं। यह कार्यक्रम समावेशी उत्सव और सामाजिक सहभागिता की भावना को मजबूत करता है।



धनतेरस पर राजवाड़ा पहुंचे महापौर भार्गव, पत्नी के साथ की खरीदारी

मिट्टी के दीपक, लाई और सजावटी सामान खरीदा, छोटे दुकानदारों का बढ़ाया उत्साह

एक सत बुलेटिन, इंदौर

धनतेरस के पावन अवसर पर शहर में दीपावली की रौनक के बीच महापौर पुष्यमित्र भार्गव अपनी पत्नी एडवोकेट जूही भार्गव के साथ इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा बाजार पहुंचे। यहां उन्होंने बाजार में लगी फुटपाथी दुकानों पर पहुंचकर छोटे व्यापारियों से मुलाकात की और उनसे दीपावली की तैयारियों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान महापौर और उनकी पत्नी ने मिट्टी के दीपक, दीये, लाई और घरों को सजाने के लिए विभिन्न सजावटी सामानों की खरीदारी की। महापौर भार्गव को अपने बीच पाकर छोटे दुकानदारों में भी उत्साह देखने को मिला। धनतेरस के अवसर पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव पत्नी एडवोकेट जूही भार्गव के साथ राजवाड़ा स्थित बाजार पहुंचे। उन्होंने फुटपाथी दुकानदारों से मुलाकात कर मिट्टी के दीपक, दीये, लाई और सजावटी सामान खरीदा। इस दौरान उन्होंने छोटे व्यापारियों का उत्साहवर्धन करते हुए स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का संदेश दिया।उन्होंने दुकानदारों से आत्मीयता के साथ बातचीत की और उनके कारोबार के बारे में जानकारी ली। महापौर ने स्थानीय दुकानदारों से खरीदारी कर उन्हें प्रोत्साहित किया। इस दौरान उन्होंने नागरिकों से भी अपील की कि वे त्योहारों के अवसर पर स्थानीय बाजारों, छोटे व्यापारियों और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें। महापौर भार्गव ने कहा कि दीपावली जैसे त्योहारों की असली रौनक छोटे दुकानदारों और स्थानीय बाजारों से ही है। मिट्टी के दीपक बनाने वाले कुम्हारों, फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले व्यापारियों और छोटे कारोबारियों की मेहनत से ही त्योहारों की परंपराएं जीवंत बनी रहती हैं। इन छोटे व्यापारियों के साथ हजारों परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है। ऐसे में स्थानीय दुकानदारों से खरीदारी करना उनके परिवारों की आर्थिक मजबूती में सहयोग करने जैसा है। उन्होंने कहा कि त्योहारों पर स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों को अपनाना हमारी परंपराओं और संस्कृति को आगे बढ़ाने का भी माध्यम है। मिट्टी के दीये न केवल दीपावली की पारंपरिक पहचान हैं, बल्कि स्थानीय कारीगरों की मेहनत और हुनर का प्रतीक भी हैं। धनतेरस के अवसर पर राजवाड़ा और आसपास के बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की आवाजाही बनी रही। दीपावली से जुड़ी अन्य वस्तुओं की खरीदारी होती नजर आई। महापौर भार्गव ने बाजार पहुंचकर स्थानीय व्यापारियों का उत्साह बढ़ाया और नागरिकों को भी स्थानीय बाजारों से खरीदारी कर छोटे कारोबारियों के साथ त्योहार की खुशियां साझा करने का संदेश दिया।



महापौर मालती राय ने निगम आयुक्त के साथ की व्यवस्थाओं की समीक्षा

दीपावली पर सफाई, पेयजल और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**



दीपावली सहित अन्य त्योहारों पर शहर में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाए रखने के लिए नगर निगम विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। महापौर मालती राय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि त्योहारों के दौरान साफ-सफाई, पेयजल और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था सुचारू रखी जाए। साथ ही शहर के सभी फव्वारों का संचालन सुनिश्चित करने और सड़कों के रेस्टोरेशन व मरम्मत कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार कराने के निर्देश दिए।

महापौर मालती राय ने शनिवार को निगम मुख्यालय अटल भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार की उपस्थिति में दीपावली सहित अन्य त्योहारों पर की जाने वाली व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में समस्त अपर आयुक्त, उपायुक्त एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान महापौर और निगम आयुक्त ने साफ-सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, फव्वारों तथा सड़कों के रेस्टोरेशन और संधारण कार्यों की जानकारी ली। महापौर ने निर्देश दिए कि बाजारों, प्रमुख स्थानों और शहर के सभी क्षेत्रों में नियमित रूप से बेहतर सफाई कराई जाए। कचरा प्रबंधन भी निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए।उन्होंने नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में और उचित दबाव के साथ पेयजल उपलब्ध कराने तथा सभी स्ट्रीट लाइट चालू रखने को कहा। शहर में स्थापित फव्वारों का नियमित संचालन करने के साथ सड़कों की मरम्मत और रेस्टोरेशन कार्यों की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

महापौर ने कहा कि त्योहारों के दौरान नागरिक सुविधाओं में किसी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए और शहरवासियों को असुविधा का सामना न करना पड़े।

जेल-राजस्व और ऊर्जा विभाग का कामकाज ठप, 4-5 दिन तक ऑनलाइन सेवाएं बहाल होने की उम्मीद

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**



मध्यप्रदेश के सरकारी विभागों की साइबर सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। साइबर अटैक की आशंका के चलते प्रदेश के 30 से ज्यादा सरकारी विभागों की वेबसाइट और पोर्टल पिछले एक सप्ताह से बंद हैं। इनमें जेल, राजस्व, ऊर्जा, उद्योग और सहकारिता जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं। वेबसाइटें बंद होने से विभागीय कामकाज प्रभावित हो रहा है। ऑनलाइन सेवाएं ठप होने के कारण फिलहाल सरकारी कामकाज ऑफलाइन माध्यम से किया जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक, मध्यप्रदेश साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने सरकारी वेबसाइटों की सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की थी। इसमें बताया गया कि कई विभागों की वेबसाइट पुराने पीएचपी वर्जन और फ्रेमवर्क पर संचालित हो रही हैं। इनमें सुरक्षा संबंधी खामियां हैं, जिनका फायदा उठाकर हैकर सिस्टम में सेंध लगा सकते हैं। एडवाइजरी के बाद संभावित साइबर हमले और डेटा की सुरक्षा को देखते हुए संबंधित वेबसाइटों को एहतियातन बंद करने का फैसला लिया गया।

हालांकि, अभी तक किसी सफल साइबर हमले या डेटा चोरी की पुष्टि की जानकारी सामने नहीं आई है। वेबसाइट बंद होने का असर कई महत्वपूर्ण विभागों पर पड़ा है। इनमें गवर्नमेंट प्रेस, जेल विभाग, राजस्व विभाग, ऊर्जा विभाग, उद्योग विभाग और सहकारिता विभाग प्रमुख हैं। इनके अलावा भी 30 से ज्यादा सरकारी वेबसाइट और पोर्टल प्रभावित बताए जा रहे हैं। ऑनलाइन व्यवस्था बंद होने से विभागों को रोजमर्रा के कामकाज में परेशानी हो रही है। नागरिकों और हितग्राहियों को भी ऑनलाइन सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। विभागों में फिलहाल ऑफलाइन प्रक्रिया के जरिए काम निपटाए जा रहे हैं।

सुरक्षा खामियों को दूर करने के लिए संबंधित विभागों के तकनीकी विशेषज्ञ और एमपीसीईआरटी की टीम काम कर रही है। सर्वर को अपग्रेड किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, सुरक्षा मानकों को दुरुस्त करने में अभी 4 से 5 दिन का समय और लग सकता है। इसके बाद ही वेबसाइटों को दोबारा शुरू करने की स्थिति बन पाएगी। इसका मतलब है कि अगले कुछ दिनों तक सरकारी विभागों की ऑनलाइन सेवाओं के लिए आम लोगों को इंतजार करना पड़ सकता है।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने दीपावली पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएँ

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने दीपावली के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि दीपावली



का पर्व अंधकार पर प्रकाश, असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। यह पर्व हमें जीवन में सद्भाव, प्रेम, सहयोग और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कामना की है कि दीपावली का प्रकाश प्रत्येक परिवार के जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य और खुशहाली लेकर आए। भगवान श्री गणेश एवं माता लक्ष्मी की कृपा से प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो तथा सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार हो। प्रदेशवासियों से दीपावली का पर्व पारंपरिक उल्लास, आपसी प्रेम और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की है।

बैंक की सीनियर मैनेजर का फोन हैक कर साढ़े पॉच लाख उड़ाये

भोपाल। अवधपुरी इलाके में स्थित आधारशिला कॉलोनी में रहने वाली बैंक ऑफ बड़ौदा की सीनियर मैनेजर को साइबर ठगो ने अपना निशाना बनाते हुए उनका मोबाइल हैक कर बैंक खाते से 5 लाख 66 हजार की रम दूसरे खातों में ट्रांसफर कर ली। महिला को ठगी का पता उस समय लगा जब एक नवंबर को उनके खाते में सैलरी आई। इसके बाद उन्होंने बैलेंस चेक किया तो रकम गायब होने का पता चला। जांच में सामने आया कि 28 अक्टूबर से एक नवंबर के बीच अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए खाते से पैसे निकाले गए हैं। शिकायत की जॉच के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

डिग्रियां ऊंची, नौकरी की मंजिल आरक्षक

मप्र पुलिस के 7500 पदों के लिए 7.54 लाख युवा मैदान में

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**



कभी इंजीनियरिंग और पीएचडी जैसी डिग्रियां हासिल करने के बाद युवा बड़ी कंपनियों, शोध संस्थानों और अफसरशाही में भविष्य तलाशते थे, लेकिन रोजगार के बदलते हालात ने नौकरी की प्राथमिकताएं बदल दी हैं। अब इंजीनियरिंग और पीएचडी करने वाले युवा भी पुलिस आरक्षक बनने की कतार में खड़े हैं। मध्यप्रदेश पुलिस की आरक्षक भर्ती के आंकड़े इस बदलती तस्वीर को सामने ला रहे हैं। 7,500 पदों के लिए 7.54 लाख आवेदन मिले हैं। इनमें करीब 10 हजार इंजीनियर और 28 पीएचडी धारक भी शामिल हैं। आरक्षक पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के मुकाबले आवेदन करने वालों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि काफी आगे है। भर्ती में 9,933 बीई डिग्रीधारकों ने आवेदन किया है। वहीं 28 ऐसे अभ्यर्थी भी हैं, जिन्होंने पीएचडी तक की पढ़ाई की है। यह आंकड़ा बताता है कि रोजगार की तलाश में युवा अब पद की शैक्षणिक पात्रता से ज्यादा नौकरी की स्थिरता को महत्व दे रहे हैं। निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, नौकरी की अनिश्चितता और भविष्य की सुरक्षा जैसे कारणों से सरकारी सेवा का आकर्षण बना हुआ है। यही वजह है कि उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद भी युवा आरक्षक जैसे पद के लिए परीक्षा देने को तैयार हैं। भर्ती के आंकड़ों के मुताबिक, 7,500 पदों के लिए 7.54 लाख आवेदन आए हैं। इस हिसाब से प्रत्येक पद पर औसतन 100 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला होगा। चयन की राह आसान नहीं है। लिखित परीक्षा से लेकर आगे की चयन प्रक्रिया तक अभ्यर्थियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। इस बार आवेदन की संख्या पिछले साल के मुकाबले कम रही है। वर्ष 2025 में आरक्षक भर्ती के लिए करीब 9.76 लाख आवेदन मिले थे, जबकि इस बार यह संख्या घटकर 7.54 लाख रह गई। यानी करीब 2.25 लाख आवेदन कम आए हैं। हालांकि, आवेदनों में कमी के बावजूद पदों के मुकाबले दावेदारों की संख्या काफी अधिक है। पुलिस आरक्षक भर्ती केवल पुलिस बल में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह प्रदेश में सरकारी नौकरी के प्रति युवाओं के रुझान की भी तस्वीर पेश करती है। इंजीनियरिंग और पीएचडी जैसी उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वालों का आरक्षक भर्ती में शामिल होना इस बात का संकेत है कि नौकरी पाने के लिए युवा अपने करियर की शुरुआती कल्पनाओं से आगे बढ़कर उपलब्ध अवसरों को प्राथमिकता दे रहे हैं।

स्वामी एक सत प्रयास जनकल्याण समिति भोपाल के लिए, प्रकाशक एवं मुद्रक, **संपादक अमित शर्मा** द्वारा ए -1 माचना कॉलोनी , शा. राजीव गांधी स्कूल के पास, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) पिन - 462016 से प्रकाशित एवं विनर प्रिंटर्स प्लाट 241-242 डायनामिक सेन्टर, एमपी नगर जोन-1 भोपाल से मुद्रित। **स्थानीय संपादक सुनील नायक**, पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार।
RNI- MPHIN/2018/76807/ E-mail-eksatbulletin@gmail.com, डाक पंजीयन नंबर MP/BHOPAL/4-501/2020-22, मार्केटिंग एवं अन्य जानकारी हेतु संपर्क करें- फोन: 0755-4515227, मोबाइल: 9691653088

